राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 271 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार, 02 अप्रैल 2021, मूल्य रु. 1.50

बंगाल में 80 और असम में 74.64 फीसदी मतदान

नई दिल्ली, (संवाददाता)। पश्चिम बंगाल और असम की 69 सीटों पर गुरुवार को दूसरे फेज के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। बंगाल में हिंसा की कुछ घटनाओं और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के बीच 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक, शाम 6 बजे तक बंगाल में 80.43 प्रतिशत और असम में 74.64 प्रतिशत मतदान हुआ है। बंगाल में पहले फेज में 79.79 प्रतिशत और असम में 72.14 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

इस बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुनाव वाले दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं ममता ने आरोप लगाया कि अमित शाह सीधे केंद्र के भेजे सुरक्षाकर्मियों को आदेश दे रहे हैं। ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है।

ममता ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोग माहौल खराब कर रहें हैं। बाहरी गुंडे वोटिंग प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मामले में दखल देने के लिए राज्यपाल से भी बात की और केंद्रीय बलों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट जाऊंगी। इसके जवाब में मोदी ने बंगाल में ही एक रैली में कहा कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। बंगाल के लोगों ने दीदी की सरकार हटाने का फैसला कर लिया है। यहां के लोग अब और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं हैं।

बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा हुआ है। यहां पर टीएमसी कार्यकताओं का आरोप है कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं, नंदीग्राम के कमलपुर के पास भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। हमले में मीडिया की गाडियों को नुकसान पहुंचा है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तानियों का काम है। जय बंगला बांग्लादेश का नारा है। उस बूथ पर एक विशेष समुदाय के मतदाता हैं, जो ऐसा कर रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि भाजपा कार्यकताओं की भारी भीड़ बूथों में घुस गई। भाजपा कार्यकर्ता ईवीएम में घालमेल करने और बूथ में धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, भाजपा ने भी कई जगह इसी तरह के आरोप तृणमूल कार्यकताओं पर लगाए हैं। इस बीच पश्चिम मेदिनीपुर केशपुर में बूथ संख्या 173 पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकताओं पर भाजपा के पोलिंग एजेंट की पिटाई का आरोप लगाया जा रहा है। पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया है। भाजपा नेता तन्मय घोष की कार में तोडफोड़ करने की भी खबर है।

बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल : मोदी

जयनगर, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जयनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। उन्होंने कहा कि ममता की बौखलाहट पहले चरण की वोटिंग के बाद और बढ़ गई है। आज दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर तरफ भाजपा ही भाजपा है भाजपा की लहर है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में बंगाल में हुए शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड मतदान में लोगों ने भाजपा को भारी समर्थन दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि भाजपा इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी। लेकिन पहले चरण जिस तरह की दमदार शुरूआत भाजपा ने की है, उससे ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में भाजपा की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि धमकी और गालियां देने वाली दीदी कह रही हैं- कूल-कूल! दीदी, तृणमूल, कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्तरंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेज कर मदद की अपील की है। जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थीं उनसे वो समर्थन मांग रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दस साल मुख्यमंत्री रहते जनता की सेवा की होती तो ये करना पड़ता क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत का जिक्र एक बार फिर जयनगर में किया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की बेटी शोवा मजूमदार जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। शोवा जी, बंगाल की उन अनगिनत माताओं, उन अनगिनत बहनों का चेहरा थीं जिन पर तृणमूल के लोगों ने अत्याचार किया। शोवा जी का वो चेहरा मेरी आंखों से उतरता नहीं है।

काला जादू और अवैध धर्म परिवर्तन पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंधविश्वास के चलन, काला जादू और अवैध व जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिक में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह अवैध धर्मांतरण और काला जादू जैसे चलन पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल कर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और लॉ मिनिस्ट्री के साथ-साथ देश भर के तमाम राज्यों को प्रतिवादी बनाया गया है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर संघ पर लगाए आरोप

अमृतसर, (एजेंसी)। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खिलाफत में आ गई है। गुरुवार को कमेटी की तरफ से जनरल हाऊस में बड़ा प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में आरएसएस की कोशिशों और गतिविधियों की निंदा करते हुए भारत सरकार को सावधान किया गया।

जनरल हाउस में प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जागीर कौर ने कहा कि आरएसएस दूसरे धर्मों और अल्पसंख्यकों की आजादी को दबा रही है। वह देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। प्रस्ताव के द्वारा भारत में सिखों सहित अल्पसंख्यकों को दबाने वाली साजिशों का सख्त विरोध किया गया है।

बीबी जागीर कौर ने कहा कि भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषायी और बहुवर्गीय देश है। इसकी आजादी में हर धर्म का बड़ा योगदान रहा है। खासकर सिख कौम ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया। लेकिन अफसोस है कि आरएसएस की तरफ से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही है। इसके तहत दूसरे धर्मों की आजादी को दबाया जा रहा है। इस प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार को सावधान किया गया कि वह आरएसएस की तरफ से शुरू की गई कोशिशों को लागू करने के लिए तत्पर होने की जगह हर धर्म के अधिकारों और धार्मिक आजादी को सुरक्षित बनाने के लिए कार्य करे। जो भी अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयत्न करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

भ्रष्टाचारी डीएमके और कांग्रेस नहीं कर सकती तमिलनाडु का विकास : शाह

चेन्नई, (एजेंसी) तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार करने आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। एक चुनावी प्रचार में अमित शाह ने डीएमके और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि हम सब लोग डीएमके और कांग्रेस पार्टी को अच्छे से जानते हैं। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है- गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जमीन हड़पना और अपने बेटे-बेटियों को आगे बढ़ाना..जनता की चिंता नहीं करना यही डीएमके और कांग्रेस का रास्ता है। शाह ने आगे कहा कि चुनाव की तिथि चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में चुनाव 6 अप्रैल को तय किया है जो भाजपा का स्थापना दिवस है। इसलिए तमिलनाडु में एनडीए की विजय सुनिश्चित है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने डीएमके और कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी डीएमके और कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु का विकास नहीं कर सकती हैं। तमिलनाडु का विकास नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन ही कर सकता है। नरेन्द्र मोदी जी के मन में तमिलनाडु और तमिल भाषा के प्रति अपार सम्मान और प्यार है। विश्व में वो कहीं भी जाते हैं, तमिल के सुवाक्यों को अपने भाषण में दोहराते हैं। तमिल मछुआरों की जितनी चिंता मोदी जी ने की है, उतनी किसी ने नहीं की है। अभी-अभी डीएमके वाले जल्लीकट्टू की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जल्लीकट्टू की बात कर रही है। ये ही राहुल गांधी हैं जिन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में जल्लीकट्टू पर बैन लगाने की घोषणा की थी। डीएमके के नेता ए राजा पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि मैंने उनका एक बयान देखा। मुख्यमंत्री जी की स्वर्गवासी माता के लिए उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है, मुझे लगता है कि डीएमके को महिलाओं के सम्मान की कोई सुध नहीं है और इस प्रकार से ओछी और नीची राजनीति करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं।

किरण योद्धा हैं और ताकतवर होकर निकलेंगी : अनुपम

नई दिल्ली, (संवाददाता)। बॉलीवुड की असाधारण अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद किरण खेर के कैंसर पीड़ित होने की खबरों से फिल्मी दुनिया सहित पूरे देश में लोगों में दुख फैल गया। ऐसे में अब अभिनेता और किरण के पति अनुपम खेर ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। अनुपम और उनके बेटे सिकंदर खेर ने किरण खेर की बीमारी को लेकर बयान जारी किया है। इस बयान में अनुपम ने पत्नी को फाइटर बताया है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए अनुपम खेर लिखते हैं, अफवाहें लोगों को परेशान ना करें इसलिए मैं और सिकंदर सभी को बताना चाहते हैं कि किरण मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित पाई गई हैं, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। वह फिलहाल अपना इलाज करवा रही हैं और हमें पता है कि वह इससे पहले से ज्यादा ताकतवर होकर बाहर निकलेंगी।

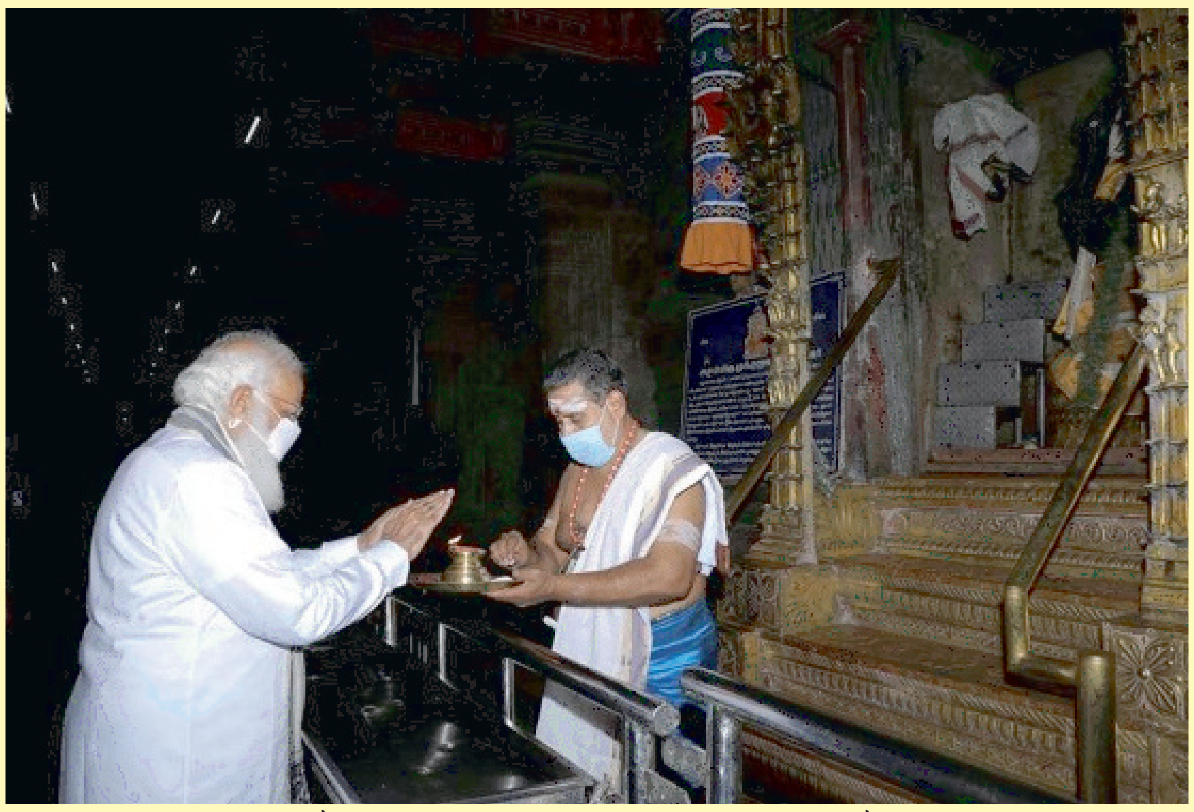

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरै में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए एक चुनाव प्रचार रैली के लिए अपनी यात्रा के दौरान मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा करते हुए।

कार्टून

कुलपति ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

'टीएमसी नेता से मिली धमकी, सुरक्षा हो सुनिश्चित'

नई दिल्ली, (संवाददाता)। विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल ने उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी है। चक्रवर्ती ने स्थानीय समाचार पत्रों की खबरें संलग्न करते हुए आरोप लगाया कि मंडल ने उन्हें ऐसा सबक सिखाने की धमकी दी, जिसे वह जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने 24 मार्च को लिखे पत्र में कहा, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने चुनाव के बाद मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। चक्रवर्ती ने आगे कहा, इन परिस्थितियों में, मेरा आपसे अनुरोध है कि परिसर में किसी अप्रिय घटना को होने से रोकने और मेरी एवं मेरे परिजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

बता दें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। गौरतलब है कि मंडल ने 23 मार्च को एक जनसभा के दैरान कहा था कि एक पागल व्यक्ति विश्वभारती के कुलपति की कुर्सी पर बैठा है, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद दिन में विश्वविद्यालय के सभी द्वार बंद रखता है। मंडल ने स्पष्ट रूप से चक्रवर्ती का जिक्र करते हुए कहा था, हम चुनाव के बाद आपको लोकतांत्रिक माध्यमों से ऐसा सबक सिखाएंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। कुलपति के पत्र के संबंध में प्रतिक्रिया लेने के लिए मंडल से संपर्क नहीं हो सका।

हालांकि तृणमूल नेता ने कहा कि उन्होंने चक्रवर्ती के खिलाफ स्थानीय लोगों के बढ़ते गुस्से को केवल दशार्या था और उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी।

बता दें कि विश्व भारती के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती का विवादों से पुराना नाता रहा है। अभी दो हफ्ते पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसे लेकर वह चर्चा में रहे। दरअसल, इस ऑडियो क्लिप में वह कथित तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को बंद कराने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि, ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसमें कथित तौर पर चक्रवर्ती शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों से यह कहते सुनाई देते हैं, मैं विश्व भारती का बंद होना सुनिश्चित करूंगा, लेकिन मैं कोई धमकी नहीं दे रहा। ऑडियो क्लिप में यह भी सुना जा सकता है, विश्व भारती चोरों-डकैतों का पनाहगाह बन गया है। अन्यथा कैसे तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल कुलपति को पागल कहकर जा सकते हैं।

प्रतापगढ़ शराब कांड में 7 लोगों की जान गई, 3 गंभीर

प्रतापगढ़, (एजेंसी)। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में घटे शराब कांड के मुख्य आरोपी और प्रधान चुनाव का दावेदार डब्बू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डब्बू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से डेढ़ पेटी अवैध शराब भी बरामद किया है। डब्बू सिंह के साथ बाबू लाल, अशोक, कपिल, धमंडी को पुलिस ने दबोचा है, जबकि प्रधान प्रत्याशी पवन सिंह और शेरे अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक डब्बू सिंह और पवन सिंह आहड-बीहड़ गांव से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी थे। मंगलवार को इनके द्वारा चुनावी जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसमें डब्बू और पवन द्वारा मिलावटी शराब अपने समर्थकों को बांटी गई थी। इनकी बांटी गई जहरीली शराब पीने से ही सात व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि तीन व्यक्तियों की हालत गंभीर बनी हुई है।

आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह ने आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। पुलिस ने गैंग लीडर को भी चिन्हित कर लिया है। आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह के मुताबिक प्रधान प्रत्याशी डब्बू सिंह ने शराब पिलाई थी। अवैध मिलावटी शराब पीने से 6 लोगों की मौत और तबियत बिगड़ने पर 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आईजी केपी सिंह के मुताबिक दोषी पुलिसकर्मियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। बीट कांस्टेबल से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के साथ ही 272 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार पवन सिंह के भट्टे और राइस मिल में अवैध शराब लाकर डंप किया जाता था। वहीं से इलाके में अवैध शराब के कारोबार को संचालित किया जाता था। सभी पकडे गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। प्रतापगढ़ के कटरिया गांव में अब तक जहरीली शराब का सेवन करने से सात व्यक्ति की मौत हो गई है। जबकि 3 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में मातम और खौफ दोनों ग्रामीणों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है।

संक्षिप्त समाचार

फेसबुक से हटाए जाने के बाद इस तरीके से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने की एक्टिव होने की कोशिश

सैन फ्रांसिस्को । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में हिंसा के कारण रोक लगने के बाद अपनी पुत्रवधू लारा ट्रंप के फेसबुक पेज के माध्यम से फिर सक्रिय होने की कोशिश की। उन्होंने अपना इंटरव्यू पोस्ट किया, लेकिन फेसबुक ने उनके कंटेंट को ब्लॉक कर दिया। ज्ञात हो कि अमेरिका के कैपिटल हिल (संसद) में 6 जनवरी को हिंसा के दौरान अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही फेसबुक ने भी उनका अकाउंट अनिश्चिकाल के लिए निलंबित कर दिया है। तभी से पूर्व राष्ट्रपति इंटरनेट मीडिया के अधिकांश प्लेटफॉर्म पर निलंबित चल रहे हैं।

ट्रंप के इस बार अपनी पुत्रवधू लारा के पेज से फिर सक्रिय होने पर फेसबुक ने चेतावनी जारी की है, यदि फिर ट्रंप इस पर सक्रिय हुए तो अकाउंट सीमित कर दिया जाएगा। लारा की शादी ट्रंप के पुत्र एरिक फेडरिक ट्रंप से हुई है। ज्ञात हो कि इंटरनेट मीडिया पर रोक लगने के बाद ट्रंप ने जनता से जुड़ने के लिए अपनी एक वेबसाइट भी लांच की है।

उइगर मुस्लिमों पर रिपोर्टिंग करने वाले बीबीसी संवाददाता का उत्पीड़न, सुरक्षा कारणों से छोड़ा चीन

बीजिंग । उइगर मुस्लिमों पर रिपोर्टिंग करने वाले बीबीसी के एक पत्रकार का चीनी अधिकारियों ने इस कदर उत्पीड़न किया कि उन्हें सुरक्षा कारणों से परिवार सहित देश छोड़ना पड़ा। बीबीसी ने बुधवार को बताया कि जॉन सडवर्थ चीन में उनके पत्रकार थे। सुरक्षा कारणों से वह चीन से ताइवान पहुंच गए हैं। फरिन कॉरस्पॉडेंट क्लब ऑफ चाइना ने कहा है कि जॉन की सुरक्षा को खतरा था। उनके साथ उनकी पत्नी वोने मुरे भी हैं, जो आइरिश ब्रॉडकॉस्टर आरटीइ की कोरस्पॉडेंट हैं। जॉन ने चीन के अधिकारियों का वह सच उजागर कर दिया था, जो दुनिया से देश छिपाना चाह रहा था। जॉन को यहां पर अब धमकियां दी जा रही थीं। उनको चीन से केवल पहने हुए कपड़ों में ही देश से बाहर जाना पड़ा। जॉन नौ साल तक चीन में रहे। इस दौरान उन्होंने उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार की कई रिपोर्ट दीं। उन्हें शिनजियांग के यातना शिविरों की रिपोर्टिंग के लिए पिछले साल जॉर्ज पोल्क अवार्ड भी दिया गया था। बीबीसी के एक पत्रकार का चीन में इस कदर उत्पीड़न किया गया कि उनको परिवार समेत देश छोड़ना पड़ा है। उइगर मुस्लिमों पर रिपोर्टिंग करने वाले बीबीसी के एक पत्रकार का चीन में इस कदर उत्पीड़न किया गया कि उनको परिवार समेत देश छोड़ना पड़ा है।

बीबीसी ने बुधवार को बताया कि जॉन सडवर्थ सुरक्षा कारणों से वह चीन से ताइवान पहुंच गए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि हमने कभी जॉन को नहीं धमकाया है। उन्होंने क्यों देश छोड़ा, इसका कारण उन्हें नहीं मालूम है। हाल ही में अमेरिका ने शिनजियांग में उइगर मुस्लिम और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ चीनी कार्रवाई को नरसंहार घोषित कर दिया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अपराध हुए हैं।बीते दिनों दुनियाभर में रहने वाले उइगरों ने चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले मुस्लिमों पर सरकारी अत्याचार के विरोध में अमेरिका से गुहार लगाई थी। निर्वासित उइगरों ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर शिनजियांग के यातना कैंपों को बंद कराने की गुजारिश की थी। उइगरों के मामले में पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन चीन को चेतावनी दे चुके हैं।

पूरी तरह सेहतमंद है म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू, अब तक हिंसा में 521 की मौत

नेपिता, एजेंसियां । म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू पूरी तरह सेहतमंद हैं। सू के साथ वीडियो बैठक के बाद उनके वकील ने यह जानकारी दी। उधर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को म्यांमार छोड़ने का आदेश दिया है। एक फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद देश में विरोध -प्रदर्शनों का दौर जारी है। प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना का दमनचक्र जारी है। अब तक सेना के हाथों 521 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गत शनिवार को 141 लोग मारे गए थे।

सेना के दमन के बावजूद विरोध-प्रदर्शनों का दौर जारी है। बुधवार को एक बार फिर देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। देश के सबसे बड़े शहर यंगून में लोगों ने बर्तन और कार का हार्न बजाकर विरोध दर्ज कराया। जिस समय ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय सीएनएन का समाचार दल भी वहां मौजूद था। खास बात यह है कि सीएनएन के पूरे क्रू को सेना चारों तरफ से घेरे हुए थी। उधर, देश के सबसे बड़े सशस्त्र विद्रोही संगठन करेन नेशनल यूनियन (केएनयू) ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और थाइलैंड से करेन लोगों की मदद करने का अनुरोध किया है। बता दें कि केएनयू लड़ाकों पर म्यांमार की सेना द्वारा हमला किए जाने से सैकड़ों करेन लोगों ने भागकर थाइलैंड में शरण ली है।

म्यांमार में छिड़ सकता है भयंकर गृह युद्ध! संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत ने किया आगाह

संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टीन श्रेनर बर्गनर ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ने की आशंका है। उन्होंने इसको देखते जरूरी कदम उठाने की भी अपील की है। उनका कहना है कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने साफ किया है कि यदि इसको अभी नहीं रोका गया तो फिर पूरी दुनिया को इसको लंबे समय तक देखना और झेलना पड़ सकता है। उन्होंने इसको लेकर म्यांमार के पड़ोसी देशों को भी आगाह किया है। क्रिस्टीन ने कहा है कि इस आशंका को देखते हुए साझा प्रयासों के तहत उठाए जाने वाले सभी जरूरी कदम और मौजूद विकल्पों को तलाशा जाना चाहिए। एक वर्चुअल बैठक के दौरान क्रिस्टीन ने कहा कि सैन्य शासन द्वारा वहां पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और सेना के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या की जा रही है। उन्होंने इस दौरान म्यांमार असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स द्वारा दी गई जानकारियों को भी साझा किया। इसमें बताया गया है कि तख्तापलट के बाद से अब तक 2729 लोगों को सुरक्षाबलों द्वारा हिरासत में लिया गया है, जबकि 536 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 मार्च को म्यांमार में हुई लोगों की हत्या की भी कड़ी निंदा की गई और सैन्य शासन को उखाड़ फेंकने की भी वकालत की गई। इसमें मांग की गई कि लोकतांत्रिक सत्ता को फिर से बहाल किया जाना चाहिए और आंग सान सू की समेत सभी नेताओं को बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

आपको बता दें कि म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को सेना ने तख्तापलट कर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। इसके बाद म्यांमार के कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिन आंग ह्लेनिंग ने खुद को देश का प्रमुख घोषित करते हुए आंग सांग सू की समेत सत्ताधारी पार्टी के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया था। ह्लेनिंग का आरोप है कि नवंबर 2020 में हुए चुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली की थी। सेना की तरफ से सू की पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। देश में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद से ही वहां पर सैन्य शासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। इनमें अब तक करीब 500 से अधिक लोगों की जान सेना और सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर तरह इसकी कड़े स्वरों में निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि म्यांमार में सैन्य शासन लागू हुआ है। म्यांमार में सैन्य शासन का लंबा इतिहास रहा है। करीब 5 दशकों तक वहां पर सैन्य शासन ही रहा है। इसी वजह से म्यांमार अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग रहा और उस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगे। वर्ष 2015 में आंग सांग सू की ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की और सैन्य शासन का अंत हुआ था। इसके बाद ही म्यांमार पर से कई सारे प्रतिबंध हटा लिए गए थे और वहां पर विदेशी निवेश भी शुरू हुआ था।

कोरोना का कहर: फ्रांस में तीसरी बार लॉकडाउन की घोषणा, 4 हफ्तों तक रहेंगी पाबंदियां

पेरिस । कोरोना वायरस का कहर जारी है. वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहे फ्रांस में तीसरी बार लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. बीते बुधवार को राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने देशभर में 4 हफ्तों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. इस दौरान शिक्षण संस्थानों से लेकर कारोबार की जगह तक सब बंद रहेंगे. फ्रांस की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि यूरोप में एक बार फिर महामारी पर नियंत्रण खो दिया है.

बुधवार को टीवी कार्यक्रम के दौरान मैक्रों ने कहा हमने इन निर्णयों को देर से करने के लिए हर संभव प्रयास किया. उन्होंने कहा कि इन फैसलों को सख्ती से लेने का वक्त आ गया है. 43 वर्षीय मैक्रों ने साल की शुरुआत से ही तीसरे बड़े स्तर के लॉकडाउन से बचने की कोशिश की थी. उन्होंने दावा किया था कि अगर वे फ्रांस को बगैर लॉकडाउन लगाए महामारी से बाहर ले जाते हैं, तो वे बीते साल अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को सुधारने के लिए एक मौका दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस वीकेंड के बाद अगले तीन हफ्तों के लिए स्कूल बंद रहेंगे.

इस वीकेंड के बाद स्कूल के बच्चों के लिए एक हफ्ते तक पढ़ाई रिमोटली चलेगी. इसके बाद 2 हफ्तों की छुट्टी रहेगी. इसके बाद नर्सरी और प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे स्कूल लौट सकेंगे. जबकि, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को एक हफ्ता और डिस्टेंस लर्निंग करनी होगी. राष्ट्रपति ने कहा वायरस की रफ्तार को कम करने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है. खास बात है कि फ्रांस में फरवरी के बाद से ही रोज मिलने वाले संक्रमितों की संख्या दोगुनी होकर 40 हजार के करीब पहुंच गई है.

देश में गहन देखभाल वाले मरीजों का आंकड़ा 5 हजार को पार कर गया है. मैक्रों ने जानकारी दी है कि क्रिटिकल केयर यूनिट्स में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है. इस दौरान उन्होंने टीकाकरण को लेकर भी बात की है.

मैक्रों ने कहा कि टीकाकरण की रफ्तार को भी बढ़ाने की जरूरत है. वर्ल्डोमीटर के आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस में मरीजों का आंकड़ा 46 लाख 44 हजार 423 पर पहुंच गया है. देश में अब तक 95 हजार 640 मरीजों की मौत हो चुकी है. वहीं, एक्टिव मामलों की संख्या 42 लाख 54 हजार 145 है.

अमेरिकियों की जान लेने के मामले में तीसरे नंबर पर कोरोना, बीते साल हुई कुल 33 लाख मौतें

वॉशिंगटन । कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में बीते साल कोविड-19 से मौतों की तीसरी सबसे बड़ी वजह बनी है. इस बात की जानकारी बुधवार को सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने दी है. इसके अलावा केवल दिल की बीमारी और कैंसर की वजह से ज्यादा मौतें हुई हैं. साथ ही महामारी के चलते अमेरिका में मृत्यदर में भी इजाफा हुआ है.

अमेरिका में पिछले साल कोविड-19 महामारी समेत विभिन्न कारणों से 33 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई जो एक साल में होने वाली सर्वाधिक मौत है. कोरोना वायरस के कारण करीब 3,75,000 लोगों की मौत हुई जो 2020 में दिल की बीमारी और कैंसर से होने वाली मौत के बाद तीसरे स्थान पर है. अमेरिका में महामारी की शुरूआत के बाद से अब तक कोविड-19 के कारण 5,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत के शीर्ष दस कारणो में पहले आत्महत्या भी एक वजह थी जिसका स्थान अब कोविड-19 ने ले लिया है. रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 16 फीसदी अधिक मौतें हुयी हैं. बुधवार को न्यूज ब्रीफिंग के दौरान सीडीसी के निदेशक डॉक्टर रॉशेल वॉलेन्स्की ने कहा 2020 मे अमेरिका में करीब 33 लाख मौतें हुई हैं. कुल मिलाकर यह 2019 में हुई मौतों में 16 प्रतिशत बढ़त को दिखाता है.

सीडीसी के नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट जनवरी से लेकर दिसंबर तक डेथ सर्टिफिकेट डेटा पर आधारित थी. रिपोर्ट के अनुसार, दिल की बीमारियो के चलते बीते साल करीब 6 लाख 90 हजार लोगों की मौत हुई. वहीं, 5 लाख 98 हजार मौतों के तार कैंसर से जुड़े थे. अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 3 करोड़ 11 लाख 66 हजार 344 मामले सामने आ चुके हैं.

कोरोना की तीसरी लहर से जूझते पाक को चीन का सहारा, मिले 5.60 लाख वैक्सीन डोज

इस्लामाबाद । कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान, चीन से लगातार मदद ले रहा है. हाल ही में पहुंची नई खेप में पाकिस्तान को चीन की तरफ से बुधवार को 5 लाख 60 हजार वैक्सीन डोज मिले हैं. इसके अलावा गुरुवार को 5 लाख डोज की एक खेप और देश में पहुंच रही है. इसके बाद चीन से मिली वैक्सीन डोज का आंकड़ा 25 लाख को पार कर जाएगा. पाक में एक्टिव मामले तीसरी बार 50 हजार से ज्यादा हो गए हैं.

चीन लगातार पाकिस्तान को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन मुहैया करा रहा है. पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द डॉन की रिपोर्ट् के अनुसार, बुधवार के बाद गुरुवार को भी मुल्क में 5 लाख डोज की एक खेप पहुंच रही है. प्रधानमंत्री इमरान खान के देश में सामान्य लॉकडाउन के फैसले के बाद सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने अंतरप्रांतीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है. शाह का मानना है कि इससे वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी किया गया डेटा बताता है कि बीते 24 घंटों में 4 हजार 757 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं. वहीं, इस दौरान 78 लोगों की मौत हो गई है. देश में एक्टिव मामलों की संख्या 50 हजार 397 पर पहुंच गई है. देशभर में 3 हजार 912 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि, 412 वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल जारी है.

इससे पहले एक्टिव मरीजों के मामले में 50 हजार का आंकड़ा जून 2020 में पार हुआ था. हालांकि, बाद में मरीजों की संख्या में कमी आई और यह आंकड़ा बीते साल सितंबर में 6 हजार से कम हो गया था. इसके बाद अक्टूबर में दूसरी लहर के दौरान मामले दोबारा बढ़े और दिसंबर में एक्टिव मामले 50 हजार से ज्यादा हो गए थे. मामलों में गिरावट फरवरी में भी देखी गई थी, लेकिन तीसरी लहर में मरीज फिर बढ़े और 31 मार्च को एक बार फिर इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 50 हजार को पार कर गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन करेंगे पहली कैबिनेट बैठक, जानें क्या है इस मीटिंग का एजेंडा

वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन गुरुवार को कैबिनेटकी पहली बैठक करेंगे। राष्ट्रपति के प्रवक्ता के मुताबिक ये बैठक कोरोना महामारी से जूझ रहे अमेरिका और अमेरिकियों की मदद को उठाए गए कदमों को लेकर होगी। प्रवक्ता कहना है कि इस बैठक में राष्ट्रपति सभी मंत्रियों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श करेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस बैठक में ये भी विचार किया जाएगा कि अमेरिकन रेस्क्यू प्लान को कामकाजी परिवारों तक कैसे आगे बढ़ाया जाए और लागू किया जाए।इसके अलावा इसमें इसको लेकर जानकारी बढ़ाने और साझा प्रयासों के तहत इसको और अधिक मददगार बनाने पर भी विचार किया जाना है।

इस बैठक के कुछ और अहम बिंदु भी हैं। इनमें से एक अमेरिका में कोविड-19 महामारी से खत्म हुए रोजगारों को दोबारा शुरू। सरकार के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आपको बता दें कि बाइडन प्रशासन की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि देश में रोजगारा के अवसरों को बढ़ाकर बेरोजगारी को कम किया जा सके। व्हाइट हाउस के प्रिंसीपल डिप्टी प्रेस सेक्रेट्री कोरोना महामारी केरीन जीन पियर ने पत्रकारों को बताया है कि का अमेरिका पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा है और वहां पर लाखों लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। इसलिए अमेरिकन जॉब प्लान इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है। उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बैठक मे एक दूसरे से दूरी बनाने का नियम फोलो किया जाएगा।

आपको बता दें कि अमेरका कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित है। वहां पर अब तक कोरोना संक्रमण के 31,166,344 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 565,256 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। देश में अब तक इस महामारी से करीब 23,673,462 मरीज ठीक हुए है और यहां पर एक्टिव केस 6,927,626 हैं जिनमें से गंभीर मरीजों की संख्या 8,759 है।

पाकिस्तान मूल के जाहिद कुरैशी, जो अमेरिका में पहले मुस्लिम फेडरल जज होंगे

वॉशिंगटन । अमेरिका के कोर्ट सिस्टम में फेडरल जजशिप के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिन 11 चेहरों को नामांकित किया है, उनमें से एक नाम ज़ाहिद कुरैशी का है, जो पाकिस्तान मूल के हैं. अगर उनके नाम पर मुहर लगती है तो अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई मुस्लिम फेडरल जज के ओहदे पर पहुंचेगा. पाकिस्तान के लिए भी यह गर्व का मौका है, तो एशिया के लिए भी. यह भी उल्लेखनीय बात रही है कि बाइडेन की टीम में एशियाई और अश्वेतों को खासा प्रतिनिधित्व मिला है. इस बीच आपको बताते हैं कि कुरैशी यहां तक कैसे पहुंचे. सीनेटर कोरी बुकर ने कहा कि जज कुरैशी अमेरिका के लिए कई भूमिकाएं कुशलता से निभाते रहे हैं और अगर उनका नाम फाइनल हो जाता है, तो अमेरिका में वो इतिहास रच देंगे. इन तमाम भूमिकाओं के बारे में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले जानिए कि इस नॉमिनेशन का अर्थ क्या है.

वास्तव में फेडरल जजशिप के लिए जो 11 नामांकन किए गए हैं, उनमें से 9 महिलाएं हैं और सिर्फ दो पुरुष. इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि किसी भी व्हाइट यानी श्वेत नस्ल के जज को नामांकित नहीं किया गया है. कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार साल के कार्यकाल के दौरान पुरुषवादी और कंज़र्वेटिव तबके को कोर्ट सिस्टम में बढ़ावा दिया था. इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए बाइडेन ने आक्रामक रवैया अपनाया. इससे पहले भी कई एशियाई और अफ्रीकी या अश्वेत चेहरों को अपनी टीम में जगह देने के लिए चर्चित रह चुके बाइडेन ने इन नामांकनों को लेकर भी विविधता को बढ़ावा देकर देश की एकता को मज़बूत करने की बात कही.

कौन हैं ज़ाहिद कुरैशी– पाकिस्तान मूल से ताल्लुक रखने वाले कुरैशी का जन्म न्यूयॉर्क में ही हुआ था और उनकी परवरिश न्यूजर्सी में हुई. उनके माता पिता शाहिदा और डॉ. निसार कुरैशी पाकिस्तान से अमेरिका जाकर बसे थे और तबसे वहीं रहे. कुरैशी ने 1997 में ग्रैजुएशन करने के बाद ज्यूरी में डॉक्टर की डिग्री रटगर लॉ स्कूल से 2000 में हासिल की थी.

कैसा रहा कुरैशी का करियर– उल्टे क्रम में देखें तो साल 2019 में न्यूजर्सी में कुरैशी को मजिस्ट्रेट जज के तौर पर नियुक्ति मिली थी. इस ओहदे को फेडरल जज के तौर पर समझा ज़रूर जाता है और कह भी दिया जाता है लेकिन यह तकनीकी तौर पर पेचीदा मसला है. अव्वल तो यह नियुक्ति अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं करता इसलिए फेडरल जजशिप से यह पद अलग होता है. दूसरी खास बात यह है कि अमेरिका के संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है इसलिए जिला कोर्ट या सर्किट जज की तरह फेडरल बेंच के मेम्बर के तौर पर बताए जाने वाले इस पद को नही माना जा सकता. खबरों की मानें तो अमेरिकी सिस्टम के मुताबिक मजिस्ट्रेट जजों को कुछ मामले असाइन किए जाते हैं.

मिलिट्री से भी रहा है नाता– कुरैशी के करियर में मिलिट्री के भीतर सेवाएं देना एक खास अनुभव रहा है. आर्मी में जेएजी कॉर्प्स के लिए वो मिलिट्री प्रॉसिक्यूटर रहे थे. और करियर के शुरूआती सालों 2004 व 2006 में उन्हें इराक में भी नियुक्ति मिली थी.

क्रोएशियाई गोताखोर ने 24 मिनट 33 सेकेंड तक पानी के अंदर सांस रोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वॉशिंगटन । एक क्रोएशियाई गोताखोर ने पानी के भीतर 24 मिनट 33 सेकेंड तक अपनी सांस रोककर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. 54 साल के बुदिमीर बुडा सोबात ने ये साहसिक कारनामा करते हुए अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया. सोबात पहले से ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं, लेकिन सप्ताहांत में वह 24 मिनट और 33 सेकेंड तक अपनी सांस पानी के भीतर रोकने में कामयाब रहे.

उन्होंने सिसक शहर में एक स्विमिंग पूल में अपना नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया. इस दौरान उनकी निगरानी के लिए डॉब, डॉक्टरों, पत्रकारों और समर्थक मौजूद रहे. गौरतलब है कि पूर्व बॉडी बिल्डर सोबात ने अपने बॉडी बिल्डिंग के जुनून को दूर कर स्टैटिक डाइविंग को गले लगा लिया था और जल्द ही वो दुनिया के टॉप 10 डाइवर्स में से एक बन गए.

उन्होंने इससे पहले तीन साल पूर्व 24 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोककर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था. डेली मेल की खबर के मुताबिक, खास बात यह है कि इस बार सोबात को बॉडी ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 30 मिनट पहले स्वच्छ ऑक्सीजन लेने की अनुमति मिली थी, जो पहले नहीं मिलती थी.

लेकिन भले ही उन्हें पहले स्वच्छ ऑक्सीजन मिली हो, इसके बावजूद भी स्टैटिक एपनिया किसी के लिए भी बड़ा जोखिमभरा होता है. खासतौर पर इंसान के दिमाग के लिए, जिसे पानी के अंदर ऑक्सीजन का सामान्य स्तर नहीं मिलता है. बता दें कि 18 मिनट के बाद सोबात को भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कई तरह की परेशानी आने लगी थीं.

सोबात के अनुसार, उनकी 20 साल की बेटी सासा से उन्हें कुछ अलग और नया करने की प्रेरणा मिलती है. सासा बचपन से ऑटिज्म और मिर्गी के दौरे से पीड़ति है.

कैलिफोर्निया में गोलीबारी की घटना में चार की मौत, संदिग्ध घायल, यूएस में इस माह गोलीबारी की ये 47वीं घटना

ओरेंज कालिफ । अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया ऑफिस की बिल्डिंग पर बुधवार को हुई गोलीबारी में एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में घायल भी हुआ है। हालांकि पुलिस ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ लिया है। उसको भी पुलिस की गोली लगी है और वो घायल है। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि, दोनों की हालत के बारे में अभी तुरंत कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। लेफ्टिनेंट जेनिफर अमत के मुताबिक, गोलीबारी की ये घटना बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर हुई है।

ओरेंज के लिंकन एवेन्यू में स्थित दो मंजिला इस इमारत में शाम करीब 5:30 बजे पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। हालांकि अमत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस घटना के पीछे क्या वजह रही है। उन्हें इस बारे में भी कुछ नहीं पता है कि आखिर क्यों इस तरह का हमला किया गया और वहां पर बच्चा क्यों मौजूद था। जिस जगह पर ये इमारत है वो एक बिजनेस इलाका है। वहां पर इश्योरेंस समेत काउंसलिंग सर्विस के दफ्तर हैं। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7 बजे हालात पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। पुलिस ने इसके बाद कहा कि अब कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं घटी है। पहले भी कई बार इस तरह की घटना में कई लोगों की मौत हो चुकी है। एक जानकारी के मुताबिक इसी वर्ष अब तक इस तरह की गोलीबारी की घटना में 447 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाला हमलावर भी शामिल है। इसके अलावा करीब 325 लोग अब तक इस तरह की घटना में घायल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इसी माह में अब तक अमेरिका में गोलीबारी की छोटी-बड़ी 47 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें करीब 46 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

गौरतलब है कि अमेरिका में होने वाली इस तरह की घटनाओं के पीछे वहां का गन कल्चर सबसे बड़ी वजह है। वहां पर हथियारों की खरीद-फरोख्त पर कोई रोक नहीं है। इसलिए वहां पर हथियारों को हासिल करना कोई समस्या भी नहीं है। अमेरिका के गन कल्चर को कम करने के लिए हथियारों की खरीद-फरोख्त के नियमों में बदलाव करने को लेकर कई बार मांग भी उठी है, लेकिन इसका कोई खास नतीजा अब तक नहीं निकल सका है।

स्माल आर्म्स सर्वे 2011 के मुताबिक अमेरिका में 100 में से 88 अमेरिकी नागरिकों के पास हथियार मौजूद हैं। 2013 से 2018 के बीच अमेरिका में इस तरह की करीब 291 हुई थीं। अमेरिका के द गन कंट्रोल एक्ट 1968 के मुताबिक 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीद सकता है। वहीं 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति हैंडगन खरीद सकता है। गन कल्चर को कम करने की मांग को ठुकराया भी जाता रहा है। वर्ष 2018 में अमेरिकी संसद के स्पीकर पॉल रेयान ने अमेरिकी नागरिकों से बंदूक रखने के अधिकार को खत्म किए जाने से इनकार कर दिया था।

म्यांमार तख्तापलट: आखिर पड़ोसी देश के बिगड़े हालात ने भारत की चिंताएं क्यों बढ़ा दी?

वॉशिंगटन । म्यांमार में तख्तापलट का विरोध जारी है. इसकी आंच भारत तक भी आई है. फरवरी में हुई इस घटना के बाद नई दिल्ली के सामने नई कूटनीतिक चुनौतियां सामने आई हैं. साथ ही उत्तर-पूर्व में नया शरणार्थी संकट खड़ा हो गया है. म्यांमार में सैन्य शासन के बाद से खासी हिंसा हुई है. भारत और संयुक्त राष्ट्र लगातार हिंसा की निंदा कर रहे हैं. ऐसे में हालात को देखते हुए भारत को संतुलन बनाना जरूरी हो गया है.

भले ही भारत यह कह रहा है कि वे खासे चिंतित हैं और हालात को करीब से देख रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में चीन फैक्टर भी बना हुआ है. खास बात है कि म्यांमार में प्रदर्शन कर रहे लोग इस तख्तापलट में बीजिंग के शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं. अब भारत अपने पड़ोसी देश में चीन का प्रभाव पसंद नहीं करेगा. इतना ही नहीं म्यांमार के सैन्य शासन के साथ संबंध रखना, भारत के लिए उत्तर-पूर्वी विद्रोहियों पर नकेल कसने का भी प्रयास है.

शरणार्थी संकट

26 मार्च के एक सर्कुलर में कहा गया था कि जिला प्रशासन को खाना और आश्रय देने के लिए कैंप शुरू नहीं करने चाहिए. साथ ही सिविल सोसाइटी और एनजीओ को भी इसी तरह के आदेश दिए गए थे. यह कहा गया था कि शरण मांगने वालों को शालीनता के साथ वापस भेज दें. हालांकि, मणिपुर गृहविभाग ने इस विवादित आदेश को वापस ले लिया था. इस आदेश की सोशल मीडिया पर खासी आलोचना हुई थी.

सरकार के मुताबिक, भारत यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी और 1967 प्रोटोकॉल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है. उन्होंने कहा है कि 2011 में जारी हुई एसओपी का पालन शरणार्थी होने का दावा करने समेत ऐसे मामलों में किया जाएगा. रोहिंग्या मामले में भी भारत का यही पक्ष रहा है. सरकारों ने यह बार-बार कहा है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर उत्पीड़न से भागने वालों को शरण देने के लिए बाध्य नहीं है.

मिजोरम की यह चुनौती खास

म्यांमार के चिन राज्य से तियाउ नदी के जरिए भारत आ रहे लोग नई तरह की चुनौती पेश कर रहे हैं. ये लोग मिजोरम की बाहुल मिजो समुदाय से जुड़े हुए हैं. भारत में उनके पारिवारिक संबंध हैं और यही वजह है कि इस समुदाय पर शरणार्थियों को छोड़ने का दबाव बनाना मुश्किल हो रहा है.

म्यांमार की बॉर्डर अथॉरिटीज ने हाल ही में चम्पाई प्रशासन को पत्र लिखकर कम से कम 8 पुलिसकर्मियों को सौंपने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच संबंध बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए. ऐसे में यह भारत के लिए खासी चुनौती बना हुआ है. भारत हिंसा की निंदा के बावजूद जुंटा को निराश नहीं करना चाहता.

कयास लगाए जा रहे हैं कि तख्तापलट में चीन का समर्थन शामिल है. क्योंकि विश्वभर में निंदा के बावजूद चीन ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, चीन ने यांगून दूतावास के बाहर जारी प्रदर्शन के बीच तख्तापलट का समर्थन करने की बात से इनकार किया है. साथ ही भारत उत्तर-पूर्व में विद्रोहियों के जोखिम को लेकर भी चिंतित है. साल 2015 में भारत ने म्यांमार में सेना के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ स्ट्राइक की थी. बीते साल महामारी के दौरान म्यांमार ने विशेष फ्लाइट से 22 विद्रोहियों को वापस भेजा था. खास बात है कि उस समय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन नहीं हो रहा था.

म्यांमार में तख्तापलट के दिन भी भारत ने कहा था, हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए. हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं.

26 फरवरी को ह्न्न यानि यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेंबली ब्रीफिंग मे सरकार ने कहा था कि भारत म्यांमार के साथ जमीन और समुद्री सीमा साझा करता है और स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए काम करता है. हाल ही में म्यांमार में हुए घटनाक्रम पर भारत द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है. हम इस बात से गहराई से चिंतित हैं कि म्यांमार ने लोकतंत्र की दिशा में पिछले दशको में जो लाभ प्राप्त किए हैं, वे कम नही होने चाहिए.

एक नजर

कोरोना काल में मेट्रो में आपको इस वजह से भी देना पड़ सकता है जुर्माना, टीमों की है आप पर नजर

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले हजारों लोग अभी भी कोरोना से बचने के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उनको जुर्माना भरना पड़ रहा है। मेट्रो टीम का फ्लाइंग स्कवायड भी इन मेट्रो ट्रेनों में सफर कर रहा है और जो लोग ठीक तरह से मास्क लगाए नहीं मिल रहे हैं उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इस तरह से मेट्रो की ये टीम अब तक 2000 से अधिक लोगों से जुर्माना वसूल कर चुकी है।

जुर्माना वसूल करने के साथ ही मेट्रो स्टेशन पर हिंदी और इंग्लिश में ये कहा भी जाता है कि सभी लोग प्रॉपर तरीके से मास्क पहनें, यदि वो ठीक तरह से मास्क नहीं लगाएंगे तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेट्रो के यात्री नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं इसके लिए दिल्ली मेट्रो के फ्लाइंग स्क्वॉयड की टीम घूम रही है। इस टीम ने 31 मार्च 2021 को 674 यात्रियों को फेस मास्क ठीक से न पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने के लिए उनसे जुर्माना वसूला। इसी के साथ टीम सभी प्रोटोकॉल और विनम्रता से दूसरों का पालन करने के लिए भी कहती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालन मेट्रो ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को मास्क न लगाना और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन न करना भारी पड़ रहा है। दिल्ली मेट्रो के नियमों के मुताबिक, मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने पर 200 रुपये का चालान किया जाता है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो में यात्रा के दौरान लोग खुद नियमों का पालन करें। ऑफ पीक आवर में यात्रा करें जिससे भीड़ कम मिले। फ्लाइंग स्क्वॉड भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए अपने साथ दूसरों की भी सुरक्षा के मद्देनजर मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। डीएमआरसी के मुताबिक, 27 मार्च को ही शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने पर 684 यात्रियों का चालान किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम के कार्यकारी निदेशक (सीसी) अनुज दयाल ने लोगों से गुजारिश की है कि मेट्रो ट्रेनों में यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से जुड़े नियमों और गाइडलाइन का जरूर पालन करें।

पहले जिस तालाब में रहती थी गंदगी, लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया आकर्षण का केंद्र

बाहरी दिल्ली । नांगलोई के कमरुद्दीन नगर के जिस तालाब में फैली हुई गंदगी के कारण लोग परेशानी झेल रहे थे, आज वही तालाब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने आपसी सहयोग से इसे स्वच्छ और आकर्षक बना दिया। आज यहां गंदगी का नामोनिशान नहीं है। दरअसल, दूषित तालाब की वजह से परेशान क्षेत्रवासियों ने जब इसे स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया तब जलबोर्ड के अधिकारियों की भी इसपर नजर पड़ी और विभाग की ओर से भरपूर सहयोग मिलने लगा। इसके बाद बदहाल तालाब का कायाकल्प हो गया। गौरतलब है कि दिल्ली जलबोर्ड ने तालाबों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी ली है। इसके तहत उत्तर पश्चिमी दिल्ली के 155 तालाबों को विकसित किया जाएगा। इसी के मद्देनजर नांगलोई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौजूद बदहाल और विलुप्त होते हुए तालाबों को नया जीवन देने की योजना है। स्थानीय निवासियों के अनुसार लोगों की कोशिश को बढ़ावा देते हुए विभाग की ओर से भी कार्रवाई की गई और इसमें उन्हें मदद मिली। तालाब के पानी के ऊपर जमी हुई काई और घास को साफ करने में विभाग के अधिकारियों ने सुविधाएं उपलब्ध कराई। तालाब की स्वच्छ को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब दिल्ली जलबोर्ड की है। अधिकारियों के अनुसार तालाबों के दूषित पानी को स्वच्छ बनाने और उसे विकसित करना उनकी प्राथमिकता है।

लोगों ने दिया योगदान- क्षेत्र के निवासी अरुण कुमार ने बताया कि यह तालाब इतना अधिक दूषित था कि जानवर भी इसके पास भटकना पसंद नहीं करते थे। इसमें मौजूद जंगली घास और काई की परत के कारण इससे बहुत दुर्गंध आती थी। इस वजह से स्थानीय लोगों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोगों ने अपने व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकालकर इस कार्य में सहयोग दिया। हर किसी ने आर्थिक और शारीरिक रूप से इस कार्य में योगदान दिया।

फुस्स हो रहे आंदोलन में हवा भरने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को दिया नया लॉलीपाप

नई दिल्ली । दिल्ली की सीमा पर बीते साल नवंबर माह से चल रहा किसानों के आंदोलन से भीड़ धीरे-धीरे कम होती जा रही है। अब इन सीमाओं पर बने टेंट में एक तिहाई लोग ही दिखाई पड़ते हैं। किसान संगठन यहां लोगों को बनाए रखने के लिए रोजाना कोई न कोई नई रणनीति बनाते हैं जिससे किसान यहां जुटे रहे। अब इन धरना स्थलों पर पहले वाली व्यवस्थाएं भी नहीं रह गई हैं। लंगर का समय भी निश्चित कर दिया गया है वरना यहां 24 घंटे लंगर चलता था। जो लोग आंदोलन में शामिल नहीं थे वो यहां अपना पेट भरने के लिए ही आ जाया करते थे। यूपी गेट पर चल रहे धरना प्रदर्शन के लंगर में तो खोड़ा के एक वर्ग का सुबह शाम खाना पीना चल रहा था। जिस पर अब कुछ असर पड़ा है। यहां धरने पर बैठे किसानों ने ठंड तो किसी तरह से काट ली मगर अब गर्मी उन्हें बेचैन करने लगी है। टेंटों की शेप बदली जा रही है। अब यहां बनाए गए मंचों पर बड़े नेता भी नहीं दिखाई देते हैं। 26 जनवरी को हुए उपद्रव के बाद से आंदोलन फीका पड़ने लगा। किसान संगठन किनारे होने लगे, कई ने साथ देना छोड़ दिया। पंजाब और अन्य राज्यों से आए किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जा चुके हैं। अब यहां नौजवान किसान नहीं दिखाई देते। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों से धरना स्थल पर भीड़ बनाए रखने के लिए आसपास के इलाकों में पंचायत करके यहां आने के लिए कह चुके हैं। उन्होंने इन पंचायतों में पहुंचकर युवाओं को धरना स्थल पर आने के लिए निमंत्रण दिया मगर वो अधिक कामयाब नहीं हुआ।

अब किसान यूनियन ने किसानों में जान फूंकने के लिए एक नया शिगूफा छोड़ा है। इसके तहत अब किसानों से पैदल ही संसद मार्च तक चलने की अपील की गई है जिससे सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे। मोर्चा के नेताओं की ओर से कहा गया है कि वो जल्द ही इस पैदल मार्च की तारीख का भी ऐलान करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए किसानों को अपने वाहन से सीमा तक आना होगा, उसके बाद वो यहां से पैदल ही संसद तक जाएंगे। वहां अपना विरोध दर्ज करवाएंगे।

अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का दिल्ली में भंडाफोड़, 16 गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने पश्चिम दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ई-वाणिज्य कंपनी एमेज़न के तकनीकी सहायक बनकर अमेरिकी नागरिकों के साथ कथित रूप से ठगी करने में शामिल हैं. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आरोपियों ने अवैध तरीकों, वीओआईपी (वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) कॉल और फर्जी कॉलर आईडी के जरिए अमेरिकी निवासियों का ब्यौरा हासिल कर लिया था. पुलिस ने बताया कि इसके बाद वे एमेज़न के तकनीकी सहायक बनकर अमेरिकी निवासियों को तकनीकी सहायता देने के बहाने से उनसे संपर्क करते थे.

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पीड़ितों से करोड़ों रुपये की ठगी की हो सकती है और मामले की छानबीन जारी है. पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उर्विजा गोयल ने बताया, ÷ एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम कॉल सेंटर पहुंची, जहां कई कॉलर अंतरराष्ट्रीय कॉल करने और कॉल प्राप्त में लगे हुए थे. प्रबंधक तरनजोत सिंह और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी कृष्ण गुरुंग गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे.÷

गोयल ने बताया, ÷ पूछताछ में, उन्होंने माना है कि वे विदेशी (अमेरिकी) नागरिकों को कॉल करने में शामिल हैं और वे एमेज़न के तकनीकी सहायक बनकर वीओआईपी के जरिए उन्हें कॉल करते हैं.÷ अधिकारी ने बताया कि आरोपी पीड़ितों से पहले से रिकॉर्ड की गई धमकी भरे कॉल से ठगी करते थे और दावा करते थे कि उनके एमेज़न खातों से संदिग्ध लेन-देन हुआ है और इसे ठीक करने के नाम पर उनके साथ ठगी करते थे. पुलिस ने 25 कंप्यूटर, इंटरनेट राउटर, 18 मोबाइल फोन तथा अन्य सामान और डेटा बरामद किया है.

नई दिल्ली के राज घाट पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।

दिल्ली में सनसनीखेज वारदातः पत्नी और दो बच्चों को मारकर शख्स ने की आत्महत्या, इलाके में हड़कंप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि घर के मुखिया ने अपनी पत्नी और 2 बेटों की हत्या की है और बाद में आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, पति फांसी से लटका मिला है जबकि पत्नी और 2 छोटे बच्चे कमरे में मृत मिले हैं. पत्नी और बच?चों के शव पर चोट के निशान हैं. पति ने जिस कमरे में फांसी लगाई है, वो कमरा अंदर से बंद था. सुबह जब परिवार को घटना की जानकारी लगी तो पुलिस को सूचित किया गया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा और शव बरामद किए.शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतकों की पहचान 31 साल के धीरज यादव, धीरज की पत्नी 28 साल की आरती, धीरज के बेटे 6 साल के हितेन और 3 साल के आर्थव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, धीरज रोहिणी के नाहरपुर गांव का रहने वाला था, वह डीटीसी में बस ड्राइवर था. धीरज के घर में तीन फ्लोर हैं.

धीरज के पिता माहा सिंह और उनकी पत्नी सुदेश रानी ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं जबकि धीरज का बड़ा भाई नीरज पहले फ्लोर पर रहता है. धीरज का परिवार दूसरे फ्लोर पर रहता था.पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली में 2 वजहों से बढ़े कोरोना के मामले, आरएमएल अस्पताल के डायरेक्टर ने भविष्य के लिए भी चेताया

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के नामी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डायरेक्टर राणा अनिल कुमार सिंह ने देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 2 बड़ी बातें कही हैं। डॉक्टर राणा अनिल कुमार सिंह ने कहा है कि लोगों की लापरवाही और उदासीनता के चलते देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही के कारण ही वर्तमान में दिल्ली में ऐसे हालात बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना के टीके की दूसरी डोज लेने के बाद किसी की भी मौत की सूचना नहीं है।

लॉकडाउन के बाद शुरू हुई लापरवाही- राणा अनिल कुमार सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद देशभर में तमाम तरह की पाबंदियां हटा ली गईं। जगह-जगह समारोह भी आयोजित किए जाते रहे और अब भी हो रहे हैं। ऐसे हालात में अगर देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि इस पर लगाम लगाएं।

उन्होंने कहा कि देशभर में कोरोना के प्रति लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों ने लापरवाही की कड़ी में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के नियमों को नहीं माना। लोगों को शारीरिक दूरी के नियमों को नहीं माना और मास्क लगाने को भी तरजीह नहीं दी। उधर, दिल्ली में बुधवार को शाम छह बजे तक 25,282 लोगों को ही कोरोना का टीका लग सका। 18,474 लोगों को टीके की पहली डोज व 6808 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को थोड़ी परेशानी हुई।

बुधवार को बच्चों का रूटीन टीकाकरण होता है। इस वजह से डिस्पेंसरियों में टीकाकरण कम हुआ। मंगलवार को 41,952 लोगों को टीका लगा था। बुधवार को टीका लेने वालों में 12,637 बुजुर्ग व 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित 2489 लोग शामिल हैं।

डीएमआरसी की पहल : अब अमेजन पे से भी रिचार्ज होंगे मेट्रो यात्रियों के स्मार्ट कार्ड

नई दिल्ली । संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए यात्री अब अमेजन पे से भी अपने स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करवा सकेंगे। बुधवार को डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. मंगू सिंह और अमेजन पे के सीईओ ने विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस सेवा की शुरुआत की। यात्री अब मेट्रो में सफर करने के लिए स्मार्ट कार्ड पर 100-2000 रुपये तक का रिचार्ज करवा सकेंगे। इस मौके पर डॉ मंगू सिंह ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के बीच कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। डिजिटल ड्राइव के समर्थन में डीएमआरसी ने प्रतिबद्धता के तहत संक्रमण के प्रसार को रोकने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।

इस मौके पर अमेजन पे के सीईओ महेंद्र नेरुरकर ने कहा कि ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान को सहज बनाने के लिए लगातार नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। दिल्ली मेट्रो की जीवन रेखा है। ग्राहकों को मेट्रो कार्ड के रिचार्ज की इस सुविधा से कांटेक्टलेस सेवा का लाभ मिलेगा। मेट्रो में सफर को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित, कैशलेस और सुरक्षित बनाने की दिशा में की गई पहल से यात्रियों की परेशानियां भी कम होंगी।

अमेजन पे टैब के तहत मेट्रो रिचार्ज विकल्प पर क्लिक कर यात्री इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मेट्रो स्मार्ट कार्ड का नंबर दर्ज करने के बाद 100 से 2000 रुपये का रिचार्ज का विकल्प चुन सकते हैं।

कोरोना पर वार : दिल्ली में 500 केंद्रों पर टीकाकरण, 45 पार वालों को लगेगी वैक्सीन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना वायरस के बचाव के लिए दिल्ली सहित पूरे देश में टीकाकरण का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत करीब 500 केंद्रों पर 45 और उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों को भी टीके लगाए जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो यहां इस आयु वर्ग के करीब 65 लाख लोग हैं जिन्हें तीसरे चरण में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में करीब 25 से 30 फीसदी आबादी को इसी चरण में वैक्सीन दिया जा सकेगा। 16 जनवरी से शुरू होने वाले पहले चरण में दिल्ली में 3.6 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन दिया गया। इसके बाद बीते एक मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण के तहत 60 और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के अलावा 45 से 59 आयु वर्ग के लोगों को कॉम्बिडिटी के साथ वैक्सीन दिया गया। अब तीसरे चरण में जिस व्यक्ति की आयु 1 जनवरी, 2022 तक 45 वर्ष या उससे अधिक होगी। सुबह 9 से रात 9 बजे तक संचालित केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को दोपहर 3 बजे तक वैक्सीन दिया जाएगा। इसके बाद गैर पंजीकृत व्यक्ति रात 9 बजे तक वैक्सीन ले सकते हैं। उन्हें बस अपना आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान प्रमाण ले जाने की जरूरत होगी। अधिकारियों ने बताया कि तीसरे चरण के पहले दिन बृहस्पतिवार को राजधानी के 136 निजी अस्पतालों सहित 192 स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

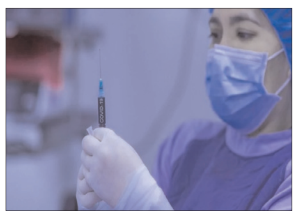

सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर टीके मुफ्त लगाए जाएंगे, जबकि 250 रुपये तक की खुराक निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध हैं। पात्र लाभार्थियों की संख्या काफी बड़ी है। हम जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करने का प्रयास करेंगे। उत्तरी दिल्ली की डीएम ईशा खोसला के अनुसार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है, जो अपने जिले के क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ताकि लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। टीकाकरण के लिए नियुक्ति को-विन 2.0 पोर्टल के माध्यम से बुक किया जा सकता है। चार से अधिक पंजीकरण करने के लिए एक मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों को प्रति खुराक 250 रुपये का शुल्क देना होगा, जिसमें 100 रुपये प्रति सेवा शुल्क भी शामिल है।

33 अस्पतालों में 220 आईसीयू बिस्तर आरक्षित - राजधानी में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने से चिकित्सीय सेवाओं पर फिर से असर पड़ सकता है। संक्रमित मरीजों को समय पर उपचार दिलाने के लिए सरकार ने अस्पतालों में बिस्तरों को आरक्षित करना शुरू कर दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने 33 प्राइवेट अस्पतालों में 220 आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इन 33 अस्पतालों में कुल 1900 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से 30 मार्च तक 608 आईसीयू बिस्तर थे, जहां संक्रमितों का उपचार चल रहा था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 838 कर दी है। वर्तमान में 346 बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं। ठीक इसी तरह कोविड वार्ड में बिस्तरों की संख्या भी 1705 से बढ़ाकर 2547 कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इन प्राइवेट अस्पतालों में राजधानी के लगभग सभी बड़े अस्पताल शामिल हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के 16 निजी अस्पताल पहले ही कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड से भर चुके हैं। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर 787 में से 298 वेंटिलेटर भर चुके हैं। 1229 में से 393 आईसीयू बेड भी फुल हो चुके हैं। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। सरकारी और निजी अस्पतालों में संक्रमितों के लिए केवल 25 फीसदी बिस्तर आरक्षित किए हैं। कुछ निजी अस्पतालों में सभी आईसीयू बेड भरे हुए हैं।

कई अस्पतालों में खाली नहीं है वेंटिलेटर- दिल्ली कोरोना वेबसाइट के अनुसार, रोहिणी में अग्रसैन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 15 आईसीयू बिस्तर, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 6, शालीमार बाग में मैक्स एसएस अस्पताल में 5, फोर्टिस अस्पताल में 5 में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है।

वेंकटेश्वर अस्पताल द्वारका, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज और महाराजा अग्रसेन अस्पताल पंजाबी बाग में भी बुधवार शाम 4 बजे तक एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं था। सरिता विहार में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 24, पश्चिम विहार में बालाजी एक्शन मेडिकल अस्पताल में 21, पंजाबी बाग में महाराजा अग्रसेन अस्पताल और शालीमार बाग में मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में सभी आईसीयू बेड (बिना वेंटिलेटर) भरे हुए हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं उठा पाई भाजपा सांसद की मौत से पर्दा

नई दिल्ली । पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा (63) की मौत से पर्दा नहीं उठा पाई है। दिल्ली पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगलवार शाम को मिल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद फाइनल ओपिनियन (अंतिम निर्णय) दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद नई दिल्ली जिले की नार्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने सांसद के विसरा को बुधवार को जांच के लिए यशवंत पैलेस स्थित एफएसएल में भेज दिया है।

नई दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सांसद रामस्वरूप शर्मा की पोस्टपार्टम रिपोर्ट मंगलवार शाम को नई दिल्ली जिले की नार्थ एवेन्यू थाना पुलिस को मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सांसद के गले पर रस्सी से दबने के लिए निशान(लेगीचर मार्क ऑन हिज नेक) हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ये लाइन खुदकुशी की ओर इशारा करती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रिजल्ट अभी आना है। सांसद की मौत कैसे हुई इसको लेकर फाइनल ओपिनियन विसरा रिपोर्ट आने के बाद दिया जाएगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विसरा जांच के लिए भेजा जाता है। नार्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद विसरा बुधवार को जांच के लिए भेज दिया। विसरा को यशवंत पैलेस स्थित एफएसएल में जांच के लिए भेज गया है। नार्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने सांसद के दोनों मोबाइलों को फोरेंसिक जांच के लिए सोमवार को भेज दिया था। गौरतलब है कि भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा 17 मार्च को बी-203 गोमती अपार्टमेंट में अपने आवास में पंखे से लटके मिले थे।

नई दिल्ली में कोविड-19 महामारी के कारण एक साल तक बंद रहने के बाद, दिल्ली प्राणी उद्यान इसे फिर से खोल दिया गया।

करोलबाग की अजमल खां मार्केट में नहीं लगेगा जाम, कोरोना को देखते हुए निगम ने उठाया ये महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली। करोलबाग का अजमल खां रोड फिर से मोटर वाहन मुक्त (एनएमवी) हो गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने तत्काल प्रभाव से एक लेन में वाहनों के परिचालन की अनुमति को वापस ले लिया है। यह आदेश पिछले वर्ष जुलाई में यहां के व्यापारियों के आग्रह पर दिया गया था।

व्यापारियों ने नगर निगम से अनुरोध किया था कि कोरोना के चलते बाजार में लोग पैदल आने से कतरा रहे हैं। इसलिए वाहनों को चलने की मंजूरी दी जाए। अप्रैल 2019 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इस मार्ग को नगर निगम ने एनएमवी सड़क घोषित किया था। इसके तहत शुरुआत में पहले एक किलोमीटर तथा बाद में 600 मीटर लंबी सड़क को वाहन मुक्त घोषित किया गया था। इस तरह पूसा रोड से देशबंधु गुप्ता रोड के बीच 1.6 किलोमीटर मीटर लंबे अजमल खां रोड को वाहन मुक्त कर दिया गया था।

इसके बाद इस रोड पर लोगों को बैठने के लिए बेंच लगाई गई थी। इसी तरह आकर्षक स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ पौधे भी लगाए गए थे, जो यहां आने वाले लोगों को अलग ही एहसास करा रहा था। यहां नगर निगम ने कई प्रयोग किए, जिसमें जगह-जगह प्लास्टिक की बोतल के लिए रिसाइकिल मशीनें भी लगाई गईं।

यातायात को रोकने के लिए सड़क में जगह-जगह बोलार्ड लगाए गए तथा वालंटियर्स की तैनाती की गई थी। यहां के दुकानदारों ने भी ग्राहकों की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल से बाजार आने-जाने के लिए गोल्फ कार्ट तक चलाए थे। यह प्रयोग परवान चढ़ता ही कि बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते लाकडाउन लग गया।

30 मार्च को नगर निगम के करोलबाग जोन के उपायुक्त हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 के तहत अजमल खां रोड पर सार्वजनिक वाहनों की अनुपलब्धता को देखते हुए पिछले वर्ष आठ जुलाई को जारी आदेश को वापस लिया जाता है, उस आदेश में सड़क के एक ओर यातायात परिचालन की अनुमति दी गई थी।

उस आदेश के वापस ले लेने के बाद से तत्काल प्रभाव से इस मार्ग पर यातायात परिचालन पर प्रतिबंध लग गया है। पहले दिन बुधवार को बड़ी संख्या में गार्ड तैनात किए गए थे, जो इस सड़क पर वाहनों को प्रवेश से रोक रहे थे।

दुकानदारों ने जताया एतराज- नगर निगम के इस आदेश से यहां के दुकानदारों में काफी नाराजगी है। अजमल खां ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव संजीव कपूर ने दावा किया कि आदेश के बाद पहले ही दिन यहां के कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ा है। अन्य दिनों के मुकाबले आधे लोग ही खरीदारी करने बाजार आए तो कारोबार भी आधा हो गया है।

उन्होंने बताया कि इसको लेकर जल्द ट्रेडर्स एसोसिएशन उपराज्यपाल व स्थानीय सांसद से हस्तक्षेप की मांग को लेकर मिलेगा, क्योंकि बिना किसी तैयारी तथा दुकानदारों को विश्वास में लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग के इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी तरह लोगों की जानकारी के लिए सूचना पट्टिका तक नहीं लगाई गई है। जाम से निजात दिलाने के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, वहीं दिल्ली में जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में यह फैसला अनुचित है।

संपादकीय

असम में तीखा होता चुनावी बिगुल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शोर में पड़ोसी असम का चुनावी समर भले दब गया हो, पर यहां भी चुनाव कम अहम नहीं हैं। यहां चुनावी समीकरण कई मायनों में बंगाल के ठीक उलट है। मसलन, बंगाल में भाजपा जहां 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं असम में उसका मिशन बहुमत हासिल करना और सरकार बचाना है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि बंगाल में उसके पास खोने को कुछ खास नहीं है, पर असम में उसका बहुत कुछ दांव पर लगा है।

भाजपा के चुनावी घोषणापत्र से दोनों राज्यों का राजनीतिक समीकरण समझा जा सकता है। पार्टी ने जहां बंगाल में सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नए नागरिकता कानून (सीएए) को लागू करने का एलान किया है, तो वहीं असम में उसने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, जबकि यहीं पर इस कानून का सबसे ज्यादा हिंसक विरोध हुआ था। असम में उसका मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व में बने सात दलों के गठबंधन से है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के अलावा कई अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। इनमें वह बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) भी है, जो हाल तक भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल था। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में यहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस नीत गठबंधनों के बीच है। बदरुद्दीन अजमल को साथ लेने की वजह से भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस को लगातार निशाना बनाते रहे हैं। अजमल को बंगाली मुसलमानों का संरक्षक माना जाता है और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ में सबसे ज्यादा तादाद ऐसे मुसलमानों की ही रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक कई बार असम का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी तरुण गोगोई के बाद उनके कद के किसी नेता का न होना है। दूसरी ओर, भाजपा के पास असम ही नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले हिमंत बिस्वा सरमा जैसे नेता हैं, जो तरुण गोगोई सरकार में लंबे अरसे तक मंत्री रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है, उसमें बदरुद्दीन अजमल ही कांग्रेस गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। इससे भाजपा को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में मदद मिलने की उम्मीद है। असम की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अस्सी के दशक से ही अहम रही है। इस बार भी सीएए-विरोधी आंदोलन की कोख से उपजी दो नई पार्टियों- असम जातीय परिषद और राइजोर दल ने हाथ मिलाया है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी इन पार्टियों के प्रदर्शन के बारे में पूर्वानुमान संभव नहीं है, लेकिन इनका बेहतर प्रदर्शन भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, तो भाजपा ने अपने घोषणापत्र और चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को दुरुस्त करने के अलावा असमिया अस्मिता, भाषा और संस्कृति की रक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, लेकिन नागरिकता कानून के मसले पर उसने आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साध ली है। दरअसल, उसे इस मुद्दे के 'बैकफायर' करने का संदेह है। ऊपरी असम क्षेत्र में करीब 45 सीटों पर मूल असमिया लोगों, यानी अहोम समुदाय का जबर्दस्त असर है। नागरिकता कानून का सबसे ज्यादा विरोध उसी इलाके में हुआ था। यही वजह है कि भाजपा का पूरा जोर एनआरसी की खामियों को सुधारने और असम के विकास पर है। सरकार में उसकी सहयोगी रही असम गण परिषद (अगप) ने भी अपने घोषणापत्र में सीएए पर चुप्पी साधते हुए असम समझौते की धारा छह को लागू करने की बात कही है। दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सीएए और एनआरसी को ही प्रमुख मुद्दा बनाया है। इसके जरिए वह अहोम समुदाय के अलावा अल्पसंख्यकों को भी साधने का प्रयास कर रहा है। राज्य के 27 में से नौ जिले अल्पसंख्यक बहुल हैं और कम से कम 49 सीटों पर इस तबके के वोट निर्णायक हैं। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इनमें से 22 सीटें जीती थीं, लेकिन तब कांग्रेस और एआईयूडीएफ के अलग-अलग चुनाव लड़ने की वजह से अल्पसंख्यक वोटों में विभाजन का फायदा उसे मिला था। मगर इस बार ये दोनों साथ हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी महिलाओं और चाय बागान मजदूरों का मुद्दा सुर्खियों में है। असम के 2.24 करोड़ वोटरों में 1.10 करोड़ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम दलों ने अपने-अपने घोषणापत्रों में इस तबके के लिए आकर्षक वायदे किए हैं। राज्य के 856 चाय बागानों में काम करने वाले 10 लाख मजदूर करीब 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस इनको लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। असम और बंगाल के चाय मजदूरों के हितों के लिए केंद्रीय बजट में 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। भाजपा ने इसका बखूबी प्रचार किया है। राज्य सरकार ने बीते दिनों इन मजदूरों की दैनिक मजदूरी 167 रुपये से बढ़ाकर 217 रुपये करने का फैसला किया था, लेकिन बागान मालिकों की याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, बागान मालिकों ने बीते सप्ताह इसे 26 रुपये जरूर बढ़ाया है, लेकिन इससे मजदूरों में नाराजगी है। दरअसल, वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इस रकम को बढ़ाकर 315 रुपये करने का वायदा किया था, लेकिन चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर, मजदूरों की इस नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जिन पांच मुद्दों की गारंटी दी है, उनमें चाय मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर दैनिक 365 रुपये करना शामिल है। असम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के अलावा कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का भी बहुत कुछ दांव पर है। भाजपा अगर बहुमत हासिल कर सरकार में लौटती है, तो एक ओर जहां पूर्वोत्तर की राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत होगी, तो वहीं वह यह भी दावा कर सकती है कि एनआरसी और सीएए के प्रति राज्य के लोगों में नाराजगी नहीं है। दूसरी ओर, कांग्रेस गठबंधन के लिए यह चुनाव पार्टी की स्थिति पर जनमत संग्रह साबित होगा।

प्रवीण कुमार सिंह

टीकाकरण में आयु सीमा की बंदिश को खत्म किया जाए तभी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है

इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जब करोड़ों लोग टीके के इंतजार में हैं, तब वे कारगर रणनीति के अभाव में खराब हो जाएं। कुछ राज्यों में तो टीकों के खराब होने की दर राष्ट्रीय औसत 6.5 प्रतिशत से भी अधिक है। इसी तरह टीकों के उपयोग की दर भी 30-35 प्रतिशत ही है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं अधिक संख्या में लोगों को टीके लगाए जा सकते हैं। यह ठीक है कि जल्द ही कुछ और टीके आने वाले हैं, लेकिन बात तब बनेगी, जब टीकाकरण में आयु सीमा की बंदिश को खत्म किया जाए। इससे ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है।

कुछ अंतराल के उपरांत कोरोना वायरस के संक्रमण ने फिर गति पकड़ ली है। चूंकि पिछले दो माह में संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई और प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या दस हजार के करीब पहुंच गई, इस कारण हर तबके के लोगो में कोरोना का भय खत्म हो गया और वे बिना सावधानी भीड़ भरी जगहों पर आने-जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। अब प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या 40 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। इन पांच राज्यों में कुल मामलों के 80 प्रतिशत मामले मिलने से यही पता चलता है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर स्पष्ट दिख रही है।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ही पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर यह अपील की कि राज्य सरकारें संक्रमण रोकने के लिए सक्रिय हों। इस अपील का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। जो राज्य चुनौती बने हुए हैं, वहां कोरोना के उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जितने होने चाहिए। चिंता की बात यह है कि राज्य सरकारों के साथ-साथ आम लोग भी कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए आवश्यक सतर्कता का परिचय नहीं दे रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों में न तो शारीरिक दूरी को लेकर सावधानी दिखाई जा रही है और न ही मास्क का समुचित इस्तेमाल करने में। यह तब है, जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना से लड़ाई में जो आत्मविश्वास मिला, वह लापरवाही में नहीं तब्दील होना चाहिए। उन्होंने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि संक्रमण गांवों तक न फैलने पाए। अगर संक्रमण गांवों तक पहुंच गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी।

राज्य सरकारों के साथ आम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पहली जितनी ही घातक थी। हालांकि भारत में अमेरिका और यूरोप की तुलना में कम लोग संक्रमित हो रहे और मरने वालों की संख्या भी कम है, लेकिन इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि इन देशों के मुकाबले खतरा कम है। भारत में रहन-सहन की जैसी स्थितियां हैं, उनके कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी न की जाए कि अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह कम संख्या नहीं है। इस तरह के शोध पर ज्यादा यकीन नहीं किया जाना चाहिए कि दक्षिण एशिया के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है, क्योंकि कोरोना वायरस अपने रूप बदल रहा है। उसके कुछ रूप कहीं अधिक घातक हो सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस के ऐसे कई बदले हुए रूप मिल चुके हैं, जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका आदि में उपजे। हालांकि अभी तक यह माना जा रहा है कि कोरोना के जो भी बदले रूप हैं, उन पर भारत में बनी वैक्सीन कारगर है, लेकिन आने वाले समय में इस वायरस के ऐसे रूप भी सामने आ सकते हैं, जिन पर ये वैक्सीन कारगर न हों। इन हालात में लोगों को वैसी ही सावधानी बरतनी चाहिए, जैसी लॉकडाउन के समय बरती गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते देश के कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। यह कोई बहुत कारगर उपाय नहीं है। रात के समय वैसे ही भीड़ कम होती है और यह मानना सही नहीं कि शहरों में लोग रात को पार्टी करने निकल पड़ते हैं। ऐसा करने वाले चंद लोग ही होते हैं। बेहतर हो कि राज्य सरकारें रात का कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाने के बजाय उन कारणों का निवारण करें, जिनके चलते कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है।

यदि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आई, जैसा कि कुछ राज्य सरकारें चेतावनी दे रही हैं तो पटरी पर आती अर्थव्यवस्था फिर पटरी से उतर सकती है। हालात को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतते हुए रोजमर्रा का जीवन संचालित करना होगा, ताकि कामकाज न रुके और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर चलती रहे। राज्य सरकारों को चाहिए कि वह लोगों को सावधानी बरतने के लिए चेताए और साथ ही इस महामारी को नियंत्रित करने में जुटे सरकारी अमले की चौकसी बढ़ाए। यह इस अमले की जिम्मेदारी है कि वह पहली जैसी सक्रियता से महामारी को सिर उठाने से रोके।

इस अमले को इसलिए उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व को यह दिखा दिया है कि भारत में कोरोना से लड़ने की क्षमता है। आज भारत में बनी दोनों वैक्सीन-कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। भारत न केवल दूसरे देशों को वैक्सीन दे रहा है, बल्कि अपने लोगों का टीकाकरण भी कर रहा है।

भारत में अभी तक करीब चार करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है, लेकिन महामारी को नियंत्रित करने और इसके फैलाव को रोकने के लिए अभी बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करना होगा। टीकाकरण में सुस्ती स्वीकार्य नहीं। यह ढिलाई का ही प्रमाण है कि केंद्र की ओर से राज्यों को पर्याप्त संख्या में टीके भेजने के बाद भी वहां अपेक्षित संख्या में टीके नहीं लग पा रहे हैं। जब यह मांग तेज हो रही है कि हर आयु वर्ग के लोगों को टीका लगवाने की छूट दी जाए, तब यह ठीक नहीं कि कई राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि टीका लगवाने गए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है या फिर तय संख्या में लोगों के न पहुंचने के कारण टीके खराब हो जा रहे हैं।

इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जब करोड़ों लोग टीके के इंतजार में हैं, तब वे कारगर रणनीति के अभाव में खराब हो जाएं। कुछ राज्यों में तो टीकों के खराब होने की दर राष्ट्रीय औसत 6.5 प्रतिशत से भी अधिक है। इसी तरह टीकों के उपयोग की दर भी 30-35 प्रतिशत ही है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं अधिक संख्या में लोगों को टीके लगाए जा सकते हैं। यह ठीक है कि जल्द ही कुछ और टीके आने वाले हैं, लेकिन बात तब बनेगी, जब टीकाकरण में आयु सीमा की बंदिश को खत्म किया जाए। इससे ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है।

बदल रहे हैं समीकरण

चीन और ईरान के बीच बीते शनिवार को हुआ 25 वर्षीय समझौता न केवल इस पूरे इलाके की भू-राजनीति को बल्कि दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को भी बहुत गहराई से प्रभावित करने वाला है। समझौते के मुताबिक ईरान में चीन अगले 25 वर्षों में 40,000 करोड़ डॉलर का निवेश करने वाला है। बदले में उसे ईरान से सस्ती कीमत पर भारी मात्रा में तेल की सप्लाई मिलती रहेगी। ध्यान रहे, ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। विश्व के कुल तेल भंडार का 10 फीसदी उसके पास है। ईरान और चीन दोनों अभी अलग-अलग स्तरों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए प्रतिबंधों के चलते ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है, हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद इन प्रतिबंधों के शिथिल होने की संभावना बढ़ी है। दोनों पक्षों में इस पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। अमेरिका प्रतिबंध उठाए जाने से पहले ईरान से अपनी कुछ शर्तें मनवाना चाहता है जबकि ईरान का कहना है कि पहले प्रतिबंध उठाए जाएं तभी बाकी मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।

इस बीच समझौते पर दस्तखत होने से कुछ ही दिन पहले चीन और रूस, दोनों ने अमेरिका से आग्रह किया कि वह जितनी जल्दी हो सके ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध बिना शर्त वापस ले। जाहिर है, चीन के साथ समझौते के बाद ईरान और अमेरिका में प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनना पहले के मुकाबले कठिन हो गया है। बहरहाल, इस समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू एक रणनीतिक गोलबंदी का है। चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की का आकार लेता हुआ गठबंधन वैसे तो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन मौजूदा समीकरणों को देखते हुए भारत के भी कुछ अहम हित इससे प्रभावित हो सकते हैं। खासकर इसलिए भी कि पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकी ने रूस जैसे मित्र देश को आशंकित कर दिया है। दूसरी बात यह कि चीन अगर अगले 25 वर्षों तक ईरान में टेक्नॉलजी, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस आदि क्षेत्रों में भारी निवेश करने वाला है तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान की उस पर निर्भरता बढ़ेगी और आने वाले दौर में वह चीन के एक विश्वस्त सहयोगी के रूप में उभरेगा। उसके माध्यम से चीन न केवल पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करेगा बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत के लिए मौजूद अवसरों को कम करके कश्मीर में भारत की मुश्किलें बढ़ाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट और उसे फीड देने वाली परिवहन व्यवस्था को विकसित करने में भारत अपनी काफी पूंजी लगा चुका है। देखना होगा कि चीन-ईरान समझौते का कोई विपरीत प्रभाव इसपर न पड़े। कुल मिलाकर यह समझौता भारतीय राजनय के लिए कई मोर्चों पर कठिन चुनौतियां लेकर आया है।

कहां गई पानी की बर्बादी को रोकने का प्रयास करने वाली सोच

बचत हमारी थाती रही है। पूर्वजों के संस्कारों से यह संस्कृति बचपन में ही मिसरी की तरह हम सबमें घुल जाती है। दुनिया भर के देशों के सकल राष्ट्रीय बचत के आंकड़ों के बनिस्पत भारतीयों का फीसद इस मामले में बेहतर होना इसकी तस्दीक करता है। बचपन में ही हमें गुल्लक दिया जाता था जिसमें हम अपनी पॉकेट मनी या बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसा, मौसी आदि के दिए रुपयों को जमा कर देते थे। फिर जरूरत पड़ने पर उन जमा पैसों से अपनी उम्र की हैसियत से कोई बड़ा काम कर लेते थे। अम्मा चावल पकाने के लिए जब उसे डेहरी से थाली में निकालती थीं, तो परिवार के रोज की खुराक का चावल निकालने के बाद एक मुट्ठी चावल फिर थाली से निकालकर उस पात्र में डाल देती थीं। खेतों में से जब फसल कटकर सारा अनाज घर में आता था, तो साल भर के खाने और बेचने के लिए अलग निकालकर आपातकाल का कोटा बखार (परंपरागत भंडारण स्थल) में रख दिया जाता था। दरअसल लोगों को यह समझ थी कि आने वाले दिनों में पता नहीं सूखा, बाढ़ या क्या प्रकोप आ जाए। ये उन दिनों में अपने अस्तित्व को कायम रखने की सहज सोच थी। पता नहीं ये सोच आज कहां सरक गई? पानी जैसे अनमोल प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी और उससे उपजा संकट उस सोच से तो कतई मेल नहीं खाता दिख रहा है। जल संकट की तस्वीर निरंतर भयावह होती जा रही है। आरंभ में तो किसी देश के महज कुछ जिले ही डार्क जोन में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो जाता है। हर स्रोत में मिलने वाले पानी में प्रदूषण का विस्तार थम नहीं रहा है। आखिर हम कब चेतेंगे? भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश की जल जरूरत एक तो बड़ी है, ऊपर से तेज विकास इस जरूरत में उत्प्रेरक का काम करती है। इस प्रकार बचत की खत्म होती सोच जल संकट को आग में घी की तरह भयावह कर रही है।

पानी ऐसा तरल है जिसका कोई विकल्प नहीं। अगर गला सूखा हो तो कोई भी द्रव इसका विकल्प नहीं बन सकता। फौरी राहत तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन गले को तर करने के लिए आपको पानी ही पीना पड़ेगा। तमाम तकनीकी उन्नयन के बावजूद आज तक हम जल का कोई विकल्प नहीं पेश कर सके हैं। फिर किस चीज पर इतना गुमान कर रहे हैं कि खत्म होने दो, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल हम खुद को धोखे में रख रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारा चाल-चलन ऐसा ही रहा तो हमारी पीढ़ियों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जब देखते हैं कि हमारा पड़ोसी खूब पानी की बर्बादी कर रहा है तो एक नई सोच घर कर जाती है कि सिर्फ एक मेरे कम खर्चने से पानी थोड़े ही बचेगा। भले ही सौ फीट नीचे बोरवेल करवाना पड़े, लेकिन जब मोटर की बटन दबाते हैं और पानी की धार फूट पड़ती है तो जल किल्लत की सारी सोच काफूर हो जाती है। यह तब है जब हमने पढ़ रखा है कि दुख में सुमिरन सब करै, सुख में करे न कोय। पानी की धार फूटने के उस सुख में जल संकट भला किसे याद रहेगा। दरअसल हमने बचपन में पढ़ी कौवे वाली कहानी पर तो पूरा अमल किया। पानी तलहटी में कितनी ही गहराई में चला जाए, लेकिन उसे खींचने का जुगाड़ करते रहे, परंतु पानी नीचे क्यों गया, इस बात की कभी फिक्र नहीं की। अगर फिक्र की होती तो गहराई से पानी खींचने की इतनी मशक्कत नहीं करनी होगी। जिंदगी भर हम कौवा ही बने रहे और पानी को ऊपर उठाने के लिए कंकड़ डालते रहे। हमसे तो बहुत अच्छे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने भले ही आनुपातिक रूप से इतने भयावह रूप में जल संकट का सामना न किया हो, लेकिन उनकी सोच जल बचाने को लेकर संजीदा दिखती थी। जब तेज बारिश होती थी, तो दादी छत के पनारे से गिर रही पानी की तेज धार के नीचे बड़ा सा कड़ाह रख देती थीं। यह बात और है कि ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा पानी की तेज धार से होने वाले गड्ढे के निर्माण को रोकने की होती थी। लेकिन व्यावहारिक रूप में कड़ाह के उस पानी का भी अन्य घरेलू जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि उस समय पानी की उतनी किल्लत नहीं थी तो उनकी प्राथमिकता उसे बचाने से ज्यादा गड्ढे के निर्माण को रोकने की ज्यादा थी। आज हमारी प्राथमिकता उलट गई है, लेकिन पानी सहेजने को लेकर कहां शिद्दत दिखा पा रहे हैं। आज पूरा देश भूजल पर आश्रित हो चुका है। हमारी लगभग 85 फीसद जरूरत इसी स्रोत से पूरी हो रही है। पानी के इस अथाह भंडार को रिचार्ज करने के सभी स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। तालाबों का अस्तित्व खतरें में है। पहले गांवों में कुआं शान का प्रतीक था। हर घर के सामने एक कुआं जरूर होता था। उसकी जगत (किनारे की दीवार) पर बनवाने वाले का नाम लिखा होता था। लोग यह बताते समय गर्वान्वित महसूस करते थे। आज सभी घरों के सामने मौजूद कुएं समतल हो चुके हैं। ये कुएं भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के बड़े स्रोत हुआ करते थे। अगर हम प्रत्येक परिवार के पास एक कुएं का मानक मानें तो आज देश में इनकी संख्या 22 करोड़ से अधिक होनी चाहिए थी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 2.7 करोड़ कुएं और बोरवेल मौजूद हैं। इसमें 50 फीसद संख्या बोरवेल की है। सिर्फ सिंचाई के लिए बोरवेल का वर्ष 1960-61 में एक फीसद इस्तेमाल किया जाता था, जबकि 2006-07 में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 60 फीसद हो गई। कुल मिलाकर सोच बदलने का सिर्फ समय नहीं आ चुका है, बल्कि पानी की बचत, संरक्षण और संवर्धन को लेकर सबको शिद्दत से जुटना होगा।

इतिहास साक्षी है कि गोवा की आजादी के प्रथम प्रेरक सत्याग्रही डॉ. राममनोहर लोहिया थे

पणजी के सभागार में डॉ. लोहिया ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। 18 जून से आंदोलन शुरू करने की योजना बन गई। सभा स्थल पर करीब 20 हजार लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोहिया भाषण देने के लिए खड़े हुए तो प्रशासक मिराडा रिवॉल्वर लेकर खड़ा हो गया। डॉ. लोहिया ने उसको हटाया तो जनता ने पहली बार विदेशी शासक के साथ ऐसे व्यवहार का अनुभव किया। फिर डॉ. लोहिया और उनके मित्र डॉ. जूलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे देख जनता उत्तेजित हो गई। हजारों लोगों का जमघट पुलिस स्टेशन को घेर चुका था। 19 तारीख को उमड़े जनसैलाब के चलते दोनों को रिहा कर दिया गया और गोवा में भी भारत की तर्ज पर आजादी के नारे गूंजने लगे।

केंद्रीय बजट में गोवा मुक्ति आंदोलन की स्मृतियों को जीवित एवं समृद्ध बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। गोवा मुक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और संघर्ष गाथा सर्वथा भिन्न है। राज्य सरकार गोवा मुक्ति के 60 वर्ष पर भव्य आयोजन समारोह करने की योजना बना रही थी, लेकिन स्थानीय चुनावों के चलते आचार संहिता लगने एवं कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका की वजह से कोई बड़ा आयोजन नहीं हो पाया। 23 मार्च को डॉ. राममनोहर लोहिया का जन्मदिन है। लिहाजा उनके नाम से निर्मित लोहिया मैदान में एक कार्यक्रम है। डॉ. लोहिया स्वयं अपना जन्मदिन मनाने से परहेज करते थे, क्योंकि इसी दिन सरदार भगत सिंह एवं साथियों का शहीदी दिवस भी है। जिसको वे अपने जन्म समारोह से बड़ी घटना स्वीकार करते थे। इतिहास गवाह है कि गोवा आजादी के प्रेरणादायक प्रथम सत्याग्रही डॉ. लोहिया थे।पुर्तगाल के एक जहाजी बेड़े का पहला आगमन यद्यपि वास्को डी गामा के नेतृत्व में 20 मई, 1498 में कालीकट (कोझीकोड) केरल में हुआ था, लेकिन कालीकट के राजा से अनबन के चलते पुर्तगाली 25 नवंबर, 1510 को गोवा समेत आसपास के द्वीपों पर अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गए। दक्षिण गुजरात के नगर हवेली पर भी 1779 में वे अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए। यह रोचक है कि पुर्तगाल साम्राज्य के विरुद्ध कोंकण क्षेत्र को मुक्त कराने का पहला प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, लेकिन उन्हें वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। बाद में उनके उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी ने कई बार पुर्तगाली सैनिकों को कई क्षेत्रों में मात दी। गोवा को 1961 के अंत तक क्यों पराधीन रहना पड़ा? इसके मूल में कई कारणों के साथ दो बातें मुख्य थीं। एक पुर्तगाल स्वयं डॉ. सालाजार की फासिस्ट तानाशाही में जकड़ा हुआ था और एक 'पुलिस राज्य' था। इसके साथ ही सालाजार शाही का यह अटल विश्वास था कि गोवा तथा अन्य उपनिवेशों में पुर्तगाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि 'ईश्वर और धर्म' की खातिर टिका हुआ है। इतने लंबे अर्से तक गोवा में पुर्तगाली शासन के बने रहने का बड़ा कारण भारत सरकार की यह धारणा थी कि गोवा की मुक्ति में भारत सरकार किसी प्रकार का बल इस्तेमाल नहीं करेगी। दिसंबर 1961 तक पं. नेहरू अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के चलते भारत और गोवा के स्वाधीनता प्रेमियों से दूरी बनाए हुए थे। यद्यपि गोवा में भी स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका था। यह दुर्भाग्य है कि गोवा कांग्रेस कमेटी कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी से संबद्ध थी, लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक किए गए संवैधानिक सुधारों के फलस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के अलावा अपनी अन्य सभी शाखाओं से संबंध तोड़ लिए। इस निर्णय के मूल में चाहे जो कारण रहे हों इससे गोवा के राष्ट्रवादियों का मनोबल टूटा और गोवा में राष्ट्रीय चेतना का बढ़ता हुआ ज्वार उतार पर आ गया। हालांकि बाद के दिनों में बंबई कांग्रेस अधिवेशन में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' के नारे ने समूचे देश के साथ गोवा, दमन, दीव में भी नए जीवन का रक्त संचार तेज कर दिया। मार्च 1946 तक यह स्पष्ट होने लगा था कि अब अंग्रेज अधिक समय तक भारत को अपने अधीन नहीं रख पाएंगे। उधर वे भारतीयों को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहे थे और गोवा में पुर्तगाली अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगे थे। इसी बीच मार्च 1946 में गोवा कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव ने खलबली मचा दी कि गोवा की अपनी मातृभूमि भारत से अलग अन्य कोई नियति नहीं हो सकती, क्योंकि यह उसका अभिन्न अंग है।

कांग्रेस पार्टी के अंदर समाजवादियों की बड़ी संख्या थी, जिसमें डॉ. लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, ईएमएस नंबूदरीपाद, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली आदि प्रमुख थे। 1942 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आई शून्यता को उन्होंने आंदोलन से भरने का काम किया। डॉ. लोहिया 1946 में लाहौर जेल से रिहा होकर देश भर में भ्रमण कर आंदोलन को अंतिम रूप देने में लगे थे। उनको लाहौर जेल में भयंकर यातनाएं दी गई थीं। वह आराम की खोज में गोवा के अपने पुराने मित्र डॉ. जूलियो मेनेजिस के यहां पहुंचे। वहां उनसे पणजी के कोने-कोने से आए लोग मिले। सभी ने अपने अनुभवों को डॉ. लोहिया के सामने रखा कि किस प्रकार पुर्तगाली अंग्रेजी शासकों से भी बदतर बर्ताव कर रहे हैं। डॉ. लोहिया ने 15 जून, 1946 को एक सभा बुलाने का निश्चय किया।

पणजी के सभागार में डॉ. लोहिया ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। 18 जून से आंदोलन शुरू करने की योजना बन गई। सभा स्थल पर करीब 20 हजार लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोहिया भाषण देने के लिए खड़े हुए तो प्रशासक मिराडा रिवॉल्वर लेकर खड़ा हो गया। डॉ. लोहिया ने उसको हटाया तो जनता ने पहली बार विदेशी शासक के साथ ऐसे व्यवहार का अनुभव किया। फिर डॉ. लोहिया और उनके मित्र डॉ. जूलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे देख जनता उत्तेजित हो गई। हजारों लोगों का जमघट पुलिस स्टेशन को घेर चुका था। 19 तारीख को उमड़े जनसैलाब के चलते दोनों को रिहा कर दिया गया और गोवा में भी भारत की तर्ज पर आजादी के नारे गूंजने लगे। गांधी जी ने लोहिया के आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया, लेकिन पं. नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय छवि के कारण दूरी बनाए रखी। अंततः निरंतर आंदोलन और लाखों सत्याग्रहियों के आगे भारत सरकार को भी विवश होकर सैनिक कार्रवाई कर गोवा को मुक्त कराना पड़ा। 23 मार्च को डॉ. लोहिया की स्मृति को जीवित रखने का यह प्रशंसनीय प्रयास है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस से शराब की तस्करी, बागपत में पुलिस व आबकारी विभाग से मुठभेड़ में दो तस्कर घायल

लखनऊ । गांव की सरकार के चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर प्रत्याशी हर तरह के दांव लगा रहे हैं। इस दौरान शराब की खपत भी काफी बढ़ी है और मिलावटी शराब के साथ तस्करी की शराब की शराब ने भी गति पकड़ ली है। सरकारी की सख्ती के बीच में शराब की तस्करी में एम्बुलेंस का भी प्रयोग किया जा रहा है।

बागपत में गुरुवार को पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीम को वाहनों की चेकिंग के दौरान लखनऊ के नम्बर की एक एम्बुलेंस में बड़ी मात्रा में शराब मिली। शराब के तस्कर हरियाणा से शराब ला रहे थे। लखनऊ की एक एम्बुलेंस से तस्करी की शराब लाई जा रही थी। बागपत में आज पुलिस तथा आबकारी विभाग की टीम के साथ मुठभेड़ में दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यहां के यमुना खादर में शराब तस्करों से मुठभेड़ के दौरान एक शराब तस्कर को गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने यहां दो तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ तस्करी कर लाई जा रही 55 पेटी शराब को बरामद किया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश में हरियाणा से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी शुरू हो गई है। यूपी-हरियाणा बार्डर की निवाड़ा चौकी पर पुलिस और आबकारी की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हरियाणा की ओर से आई एंबुलेंस को रोकने का इशारा किया तो शराब तस्कर एंबुलेंस को छोड़कर फरार हो गए। घेराबंदी की गई तो यमुना खादर में शराब तस्करी के आरोपितों ने पुलिस व आबकारी टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई तो शराब तस्करी के आरोपित के पैर में गोली लगी। वह जमीन पर गिर गया।

कोतवाली प्रभारी एनएस सिरोही ने बताया कि शराब तस्करी के आरोपित घायल सिकन्दर सिंह पुत्र देवीलाल निवासी सावा डेरी नार्थ दिल्ली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिकंदर के साथी संदीप शर्मा निवासी बिहार को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से तमंचा, कारतूस, खोखा तथा एम्बुलेंस में 55 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

बागपत में महिला ने ममता का गला घोंट, सात साल के बेटे व पांच साल की बेटी को उतारा मौत के घाट

बागपत । उत्तर प्रदेश के बागपत में एक कलयुगी मां ने अपने दोनों बच्चों का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। सात साल का बेटा व पांच साल की बेटी की हत्या करके महिला कमरे में ही रही। सुबह जब दूध वाले ने दूध देने के लिए दरवाजा खटखटाया तो मामले की जानकारी हुई। इस घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। साथ ही बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

छपरौली के मोहल्ला कुरैशियान में गुलाब की 11 साल पूर्व गांव कोताना निवासी अंजुम से शादी हुई थी। गुलाब हरियाणा के गुडगांव व फरीदाबाद में कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता है और हरियाणा में ही रहता है। गुलाब की पत्नी अंजुम अपने पुत्र सात वर्षीय उमर व पुत्री पांच वर्षीय अलसिफा के साथ मोहल्ला कुरैशियान में स्थित मकान में रहती है। वहीं गुलाब के चार भाई कस्बे के दूसरे मोहल्ले में रहते है।

गुरुवार की सुबह पांच बजे दूधिया भूरा दूध लेकर गुलाब के मकान पर पहुंचा। भूरा के अनुसार मकान के अंदर कमरे में बैठी अंजुम ने चिल्लाकर दूध नहीं लेने व दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या करने बात कही। इस पर दूधिया भागकर गुलाब के भाईयों के पास पहुंचा और घटना की जानकारी दी। इस पर गुलाब के सभी भाई व अन्य स्वजन मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंजुम को दबोच लिया। कमरे में बैठी अंजुम रो रही थी। जेठानी इमराना ने बताया कि अंजुम ने दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या की है।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ बड़ौत आलोक सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हरियाणा में गुलाब को भी घटना की जानकारी दी है। अभी तक किसी ने घटना की तहरीर नहीं दी है।

संक्षिप्त खबर

कैबिनेट की बैठक में बंपर बहाली का फैसला, 5437 पदों को स्वीकृति; 35 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना । होली के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य में इस वर्ष पांच हजार से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। सर्वाधिक नौकरी नगर विकास एवं आवास विभाग में आएंगी। इस विभाग में 4503 पद सृजित किए गए हैं। इसमें 2850 पद स्वीकृत वेतनमान वाले होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अलग-अलग विभागों के लिए कुल 5437 पद सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि हाल ही में राज्य में कई नए नगर निकाय बने हैं। इन नगर निकायों में नगरीय प्रशासन को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए एक ओर जहां मुख्यालय स्तर पर एक नया निदेशालय बनेगा वहीं नौ प्रमंडलों में क्षेत्रीय निदेशालयों का गठन भी होगा। इन निदेशालयों के संचालन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में 4503 पद सृजित किए गए हैं। जिसमें 2850 पद स्वीकृत वेतनमान वाले हैं। जिन पर 76.35 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

विधिक सेवा प्राधिकार में 39 पद सृजित- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, दिल्ली के वेबपोर्टल के परिचालन के लिए राज्य विधिक प्राधिकार पटना में एक, हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में एक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 37, कुल 39 डाटा इंट्री ऑपरेटर के स्थायी पद भी सृजित किए गए।

आइजीआइएमएस के लिए 403 पद मंजूर- मंझौल में अनुमंडलीय न्यायालय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के नौ पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में सौ संविदा पदों को प्रत्यर्पित करते हुए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पद, आइजीआइएमएस में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए 131 पद, आइजीआइएमएस कैंसर इंस्टीट्यूट में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्तर के 272 पद सृजित करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।

कोविड प्रोटोकाल तोड़ा तो पंजाब में लग सकती हैं और पाबंदियां, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा 8 को लेंगे फैसला

चंडीगढ़ । पंजाब में कोरोना के रोजाना औसत 2500 मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राज्य में कोरोना की स्थिति में अगले सप्ताह तक सुधार न हुआ तो सख्त बंदिशें लगाई जाएंगी। अगली समीक्षा बैठक आठ अप्रैल को की जाएगी।

वहीं केंद्र सरकार की ओर से कोरोना टेस्टिंग और पाजिटिव लोगों के एकांतवास को लेकर पंजाब पर लगाए गए लापरवाही के आरोपों पर पलटवार करते हुए कैप्टन ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने 45 साल तक के लोगों को टीका लगाने में दो महीने की देरी न की होती तो पंजाब में हालात बेहतर होते। पंजाब में कई पाबंदियां लागू हैं और प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में रोजाना 40 हजार सैंपलों की जांच की जा रही है। आरटीपीसीआर के जरिए 90 फीसद व आरएटी के जरिए 10 फीसद टेस्टिंग की जा रही है। प्रति 10 लाख के हिसाब से यह टेस्टिंग 1,96,667 तक पहुंच चुकी है जो राष्ट्रीय औसत 1,82,296 से ज्यादा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोरोना के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए भेजे गए 874 नमूनों में से केवल 588 की रिपोर्ट आने पर केंद्र का ध्यान खींचते हुए कहा कि 588 में से 411 नमूनों में यूके वेरिएंट और दो में एन440के पाया गया है। उन्होंने केंद्र से अपील की कि यूके वायरस के मामले सामने आने की चुनौती पर ध्यान देने की जरूरत है। कैप्टन ने सेहत विभाग को टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से बड़ी संख्या में प्रभावित जिलों में मोहल्ला स्तर पर योग्य लोगों तक पहुंच बनाई जाए। वहीं, कोरोना माहिरों की कमेटी के चेयरमैन डा. केके तलवाड़ ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बंदिशें बढ़ाए जाने की जरूरत है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े के बीच बुधवार को राहत इस बात को लेकर रही कि नए मामलों के मुकाबले में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी चुनौती बने हुए हैं। 24 घंटे में 2452 नए मामले सामने आए हैं जबकि 2788 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 56 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई। सबसे ज्यादा नौ-नौ मौतें जालंधर व होशियारपुर में हुईं। वहीं लुधियाना व पटियाला में आठ-आठ, मोहाली में पांच, कपूरथला, में चार, अमृतसर व संगरूर में तीन-तीन, फरीदकोट व मुक्तसर में दो-दो और मोगा, तरनतारन व पठानकोट में एक-एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। बुधवार को जालंधर में संक्रमण के सबसे ज्यादा 343, लुधियाना में 328, अमृतसर में 296, मोहाली में 254, पटियाला में 205, होशियारपुर में 161, बठिंडा में 144, कपूरथला में भी 144, गुरदासपुर में 127 और रोपड़ में 105 मामले सामने आए।

पंजाब में फ्री बस सेवा के लिए राज्य का पहचान पत्र दिखाना जरूरी, बाहरी राज्यों की महिलाएं बोलीं- हमें भी मिले सुविधा

लुधियाना । पंजाब सरकार ने वीरवार से महिलाओं के लिए सभी सरकारी बसों और स्थानीय निकाय विभाग की ओर से चलाई जाने वाली सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी है, लेकिन इसके लिए पंजाब का पहचान पत्र होना जरूरी होगा। पंजाब का पहचान पत्र जरूरी होने के कारण बाहरी राज्यों से यहां काम करने वाली कामगार महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

पंजाब के बड़े औद्योगिक शहरों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बठिंडा, मंडी गोबिंदगढ़ आदि में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश व झारखंड आदि राज्यों की महिला कामगार रहती हैं। यह कई दशकों से पंजाब में हैं, लेकिन कई के पास अभी पंजाब से जुड़ा पहचान पत्र नहीं होने से उन्हें मुफ्त बस सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। बाहरी राज्यों से आने वाली महिला कामगारों ने इस बात पर रोष जताया कि उन्हें मुफ्त सफर की सुविधा नहीं दी जा रही। शेरपुर फौजी कॉलोनी निवासी राजकुमारी सोनिया कुशवाहा, दर्शना देवी आदि ने कहा कि सरकार भेदभाव कर रही है जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार यह निर्देश वापस ले कि दूसरे राज्यों के पहचान पत्र पर फ्री सफर नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग यहां के औद्योगिक इकाइयों में काम कर अपने परिवार को पालते हैं, इसलिए उन्हें फ्री बस सफर का सेवा देना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ ही मुख्य सचिव आरके तिवारी ने लखनऊ में ली वैक्सीन की डोज

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण देश के साथ प्रदेश में एक बार फिर से से रौद्र रूप धारण कर रहा है। इसी बीच लखनऊ के साथ प्रदेश के जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का काम गति पकड़ चुका है।

लखनऊ में गुरुवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उनकी पत्नी नम्रता पाठक, मुख्य सचिव आरके तिवारी तथा अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने पत्नी के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। मुख्य सचिव के साथ उनकी पत्नी अर्चना तिवारी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली।

प्रदेश के अस्पताल भी हाई अलर्ट पर ़- कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी जगह पर मरीजों के साथ ही उनके तीमारदारों का भी कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सभी चिकित्सकों का अवकाश रद कर दिया गया है।

लोहिया इंस्टीट्यूट में नई व्यवस्था- लोहिया इंस्टीट्यूट में आज से नई व्यवस्था लागू की गई है। यहां पर अब सभी की कोविड जांच को जरूरी कर दिया गया है। मरीज के साथ अब तीमारदार को भी कोविड टेस्ट करवाना होगा।

बिना मास्क आने पर कड़ी कार्रवाई- किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज से बिना मास्क परिसर में आने पर कार्रवाई होगी। यहां पर बिना मास्क के किसी के भी पकड़े जाने पर उसको 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। यह नियम डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ तथा रेजिडेंट पर भी लागू होगा। इसके साथ ही मरीज और उनके परिजनों पर भी यह नियम लागू होगा।

राज सिन्हा ने मांगी माफी, विधायक और धनबाद पुलिस के बीच का विवाद खत्म

गोरखपुर । गोरखपुर में बाइक सवार बदमाशों ने इलेक्ट्रानिक्स दुकानदार शंभु शरण मौर्य व उनके कर्मचारी संजय पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात बुधवार की रात साढ़े आठ बजे गगहा चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर हुई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने गोरखपुर-वाराणासी राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान रोडवेज की बसों पर पथराव भी हुआ। पुलिस के आश्वासन पर करीब डेढ़ घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। पुलिस हत्या की वजह और कातिलों का पता लगाने में जुटी है।

ताबड़तोड़ फायरिंग कर की हत्या

कोठा गांव निवासी 35 वर्षीय शंभु शरण मौर्य ने गगहा-जानीपुर मार्ग पर मकान बनवाया है। इसी में उन्होंने टीवी, फ्रिज की दुकान भी खोली है। गोला, लाहीडाड़ी के 42 वर्षीय संजय पाण्डेय उनके यहां कर्मचारी थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुधवार को शंभु और संजय दुकान पर बैठे थे। बाइक सवार नकाबपोश दो बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर छह राउंड गोली चली। इसमें से चार गोली शंभु जबकि दो संजय को लगी। मौके पर पांच खोखे मिले हैं। शंभु को सीने, सिर, चेहरे व गर्दन में गोली लगी है, जबकि संजय को गर्दन व सिर में गोली लगी है। बताते हैं कि गोली चलाने वाला बदमाश बाइक पर पीछे बैठा था। गगहा पुलिस शंभु व संजय को जिला अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने इसके बाद हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया।

एसपी ने कहा

पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एके सिंह ने बताया कि आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। परिवार के लोगों से बात की जा रही है। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

सीसीटीवी फुटेज के लिए एक्सपर्ट की मदद लेगी पुलिस

शंभु की दुकान में तीन सीसीटीवी लगी हैं। लेकिन डीबीआर लाक होने के कारण पुलिस फुटेज नहीं देख पा रही है। ऐसे में पुलिस एक्सपर्ट की मदद लेगी। पुलिस का कहना है कि एक्सपर्ट की मदद से सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा।

पांच वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत, फतेहगढ़ जेल से रिहा

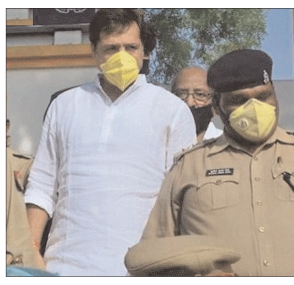

लखनऊ । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के मामले में नामजद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पांच वर्ष पुराने मामले में जमानत मिल गई है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में जमानत का आदेश मिलते ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह को रिहा कर दिया गया।

जौनपुर के पांच साल पुराने मामले में लगभग तीन सप्ताह से फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्हें गुपचुप तरीके से धनंजय सिंह को समर्थक लेकर निकल गये और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक ने धनंजय सिंह के रिहा होने की पुष्टि की।

पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में हुई हत्या के मामले में बाहुबली धनंजय सिंह का नाम आने के बाद लखनऊ पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही थी। इसके बाद पूर्व सांसद पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस केस में पुलिस की सख्ती बढने् के बाद पांच मार्च को धनंजय सिंह ने 5 मार्च को वर्ष 2017 जौनपुर के खुटहन थाने में दर्ज मुकदमे में जमानतदार ने जमानत वापस ली थी। इसके बाद पांच मार्च को ही धनंजय सिंह ने एमपी/एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेकर नैनी जेल भेज दिया।

धनंजय सिंह को 11 मार्च को नैनी जेल से फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। इस मामले में धनंजय की तरफ से दूसरे जमानतदारों की जमानती पत्र कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद धनंजय सिंह को बुधवार को फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया।

लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। धनंजय सिंह की कोर्ट में पेश जमानत पत्रावली के साथ ही फतेहगढ़ जेल से रिहाई पूरी तरह से गोपनीय रही। अजीत सिंह हत्याकांड में लखनऊ पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

धनंजय सिंह के सरेंडर के बाद लखनऊ पुलिस अभी भी अजीत सिंह हत्याकांड में कोर्ट से वारंट भी हांसिल नही कर सकी। इस केस में धनंजय सिंह की आसानी से रिहाई हो गई। धनंजय सिंह के जेल में रहने के दौरान लखनऊ पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड में अपना वारंट दाखिल ही नहीं किया, जिसकी वजह से धनंजय सिंह ने जिस जिस मामले में सरेंडर किया, उसमें जमानत मिल गई। वारंट दाखिल न करने पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि यह विवेचक और विवेचना का विषय है। फिलहाल इस मामले की समीक्षा की जाएगी।

बहुजन समाज पार्टी के जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह को 11 मार्च को प्रयागराज की नैनी जेल से सुरक्षा कारणों से यहां स्थानांतरित किया गया था। बुधवार को जमानत आदेश के आधार पर उन्हें फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक प्रमोद शुक्ला ने बताया कि धनंजय सिंह को जमानत आदेश और परवाना रिहाई के आधार पर रिहा कर दिया गया।

पंचायत चुनाव ड्यूटी में जाएंगे 2700 अधिक होमगार्ड्स, शहर में शुरू हो चुकी चयन प्रक्रिया

कानपुर । आगामी पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस के साथ होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। इसको लेकर शहर के विभिन्न थानों में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड्स का चयन किया गया है। चुनाव कार्यालय से पंचायत चुनाव के मद्देनजर 27 सौ से अधिक होमगार्ड्स की डिमांड आने की उम्मीद है। उसी के आधार पर चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले होमगार्ड्स का चयन किया जा रहा है। शहर में करीब 38 सौ होमगार्ड्स हैं।

जिनकी शहर के विभिन्न थानों, पीआरवी, विभिन्न सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के ड्यूटी लगी है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव कार्यालय से चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब 27 सौ से अधिक होमगार्ड की डिमांड आने का अनुमान है।

इसे लेकर होमगार्ड विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभिन्न थानों और सरकारी दफ्तरों में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स का चयन की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही उनकी सूची भी तैयार की जा रही है।

सप्ताह भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। वहीं चुनाव ड्यूटी जाने वाले होमगार्ड्स की आमद के लिए स्थान का भी चयन किया जा रहा है। होमगार्ड्स के जिला कमांडेंट विंध्याचल पाठक ने बताया कि चुनाव ड्यूटी जाने वाले होमगार्ड्स का चयन किया जा रहा है।

वहीं चुनाव ड्यूटी के आमद कराने को लेकर अभी निश्चित नहीं हुआ है। घाटमपुर उपचुनाव में एच-ब्लाक स्थित डॉ. चिरंजी लाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज परिसर का चयन हुआ था। काम में कोई असुविधा नहीं हुई थी। उम्मीद है कि इस बार भी इसी स्थान का आमद के लिए चयन हो।

बिहार के मामूली राजस्व कर्मचारी की दौलत देख अधिकारी हैरान, 25 से अधिक जगह खरीदी है जमीन

पटना । बिहार में पंचायत स्तर के एक मामूली सरकारी कर्मचारी की दौलत देखकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी दंग हैं। वैशाली जिले के इस राजस्व कर्मचारी ने 25 से अधिक जगह जमीन की खरीद की है। इसके पास कई कारें हैं, खुद का कोल्ड स्टोरेज है। इसके अलावा भी इस कर्मचारी ने तमाम धंधे फैला रखे हैं और बेशुमार दौलत हासिल की है।

इस मामले में निगरानी ब्यूरो ने हाजीपुर (वैशाली) के राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक मनीष कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। मनीष कुमार के खिलाफ इस मामले में निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार मनीष कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 24 फरवरी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस राशि में से उनके निजी सहयोगी पांच हजार रुपये लेकर फरार हो गए थे।

मनीष कुमार की गिरफ्तारी के बाद निगरानी ब्यूरो ने उनके खिलाफ जांच प्रारंभ की थी। जिसमें यह जानकारी सामने आई कि मनीष कुमार और उनकी पत्नी मुन्नी कुमार के नाम पर 25 से अधिक जमीन खरीद की गई है। इसके अलावा कई कार, बैंकों में निवेश की जानकारी भी निगरानी को मिली।

तेजस्वी से भाजपा का सवाल- ममता बनर्जी के सामने क्यों बंद हो गई बोलती

पटना । पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहे जाने पर बिहार भाजपा ने करारा हमला बोला है। भाजपा ने ममता की बुद्धि भ्रष्ट होने की बात कही है और इस मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव को भी घेरा है। भाजपा ने पूछा है कि बिहार के लोगों को गुंडा कहे जाने पर तेजस्वी की बोलती क्यों बंद हो गई है गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही ममता लगातार बाहरी गुंडों को बुलाए जाने की बात कहती रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने नंदीग्राम में खुद के लिए वोट मांगते हुए फिर से कहा कि बंगाल में बिहार और यूपी से आए गुंडे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा के पूर्व सदस्य आरके सिन्हा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी बुद्धि-विवेक सब खो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कल नंदीग्राम में कहा कि उन पर जितने हमले हुए, ये सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक करना उनकी पुरानी आदत है। जिससे बंगाल की जनता भलीभांति परिचित है। अभी वे जिसे हमला बता रही हैं, उससे बड़ा कोई ढोंग हो ही नही सकता। किसी का पैर टूटा हो, पैर में फ्रैक्चर हो, वह घूमता फिरे ऐसा संभव नहीं होता। सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिहार का ही नहीं बंगाल का और अपने पूर्वजों का भी अपमान किया है। ममता बनर्जी के पूर्वज भी उतने ही बिहारी थे, जितने कि हमारे पूर्वज थे। उन्होंने कहा ममता बनर्जी क्षेत्र और प्रांत के नाम पर वैमनस्य फैलाने का जो काम कर रही हैं उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा।

ममता बनर्जी द्वारा बिहार-यूपी के लोगों के खिलाफ दिए गये बयान पर तेजस्वी को घेरते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि सत्ता के लिए तेजस्वी अब इतने बेचैन हो चुके हैं कि अब उन्हें बिहार को बदनाम करने वाले राजनेताओं की चिरौरी करने में भी शर्म नहीं आती। ममता बनर्जी बिहार-यूपी के लोगों को अपराधी बता रहीं और उसपर तेजस्वी प्रतिक्रिया नहीं दें तो इससे समझा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बिहार की इज्जत और प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती। तेजस्वी के लिए अपनी राजनीति महत्वपूर्ण है और उसके लिए वे किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। रंजन ने कहा नेता प्रतिपक्ष की बंगाल में राजनीति जमाने की कोशिश पूरी तरह से ममता के रहमोकरम पर आश्रित है।

जिन पर थी अपराध रोकने की जिम्मेदारी उनकी कार कोतवाली से उठा ले गए अपराधी

गोरखपुर । देवरिया के कोतवाली परिसर से चोर एसओजी की बोलेरो उठा ले गए। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कोतवाली परिसर से पुलिस वाहन चोरी से महकमे में खलबली मच गई है। एसपी डा. श्रीपति मिश्र ने एसओजी समेत पुलिस की चार टीमें बरामदगी के लिए लगाई हैं।

यह है मामला- कोतवाली परिसर में एसओजी प्रभारी घनश्याम सिंह पुलिस विभाग की बोलेरो लेकर रात में पहुंचे। एसओजी कार्यालय के सामने वाहन खड़ा कर कुशीनगर से आए एक दारोगा के साथ कार्यालय में सो गए। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 11 बजे दो चोरों ने दरवाजा खटखटाया। कुशीनगर के दारोगा ने दरवाजा खोला तो चोरों ने एसओजी में तैनात एक दीवान के बारे में पूछा। पुलिस को शक है कि एसओजी कार्यालय में फाटक के समीप ही मेज पर रखी बोलेरो की चाबी चोरों ने उठा लिया। इसके बाद बोलेरो लेकर चले गए। सुबह बोलेरो चोरी ही खबर मिलते ही महकमे में खलबली मच गई। आनन-फानन में सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी, कोतवाल समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए और छानबीन शुरू की। एसपी डा. श्रीपति मिश्र ने बताया कि पुलिस की टीमें लगी हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही बोलेरो बरामद कर ली जाएगी।

पूरी रात पुलिस की गश्त, फिर चली गई बोलेरो- खास बात यह है कि रविवार की रात होलिका दहन था। सुरक्षा के मद्देनजर शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस व पीएसी के जवान लगाए गए थे। बोलेरो जब कोतवाली से निकली तो वहां मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों को और न ही कोतवाली गेट पर तैनात पहरा को इसकी भनक लगी। शहर व जगह-जगह तैनात पुलिसकर्मियों के सामने से ही चोर बोलेरो लेकर चले गए और इसकी भनक तक उन्हें नहीं लगी। यह एक बड़ा सवाल है।

संदेह के घेरे में एसओजी के सदस्य, होगी भूमिका की जांच

एसओजी के बोलेरो चोरी के मामले में पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बदमाश एसओजी कार्यालय से बोलेरो की चाबी उठा ले गए और दरवाजा खोलने वाले दारोगा सुभाष की नजर तक नहीं पड़ी यह एक बड़ा सवाल है। जिस दीवान के बारे में बदमाश बात कर रहे थे, वह एसओजी का चर्चित दीवान है। माना जा रहा है कि बदमाश एसओजी टीम के हर सदस्य को ठीक से जानते हैं। उन्हें इस बात का भी डर नहीं रहा होगा कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा। वह पहचान का हवाला देकर बच सकते थे। ऐसे में पुलिसकर्मी भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डा. श्रीपति मिश्र कोतवाली परिसर से बोलेरो कैसे चोरी हो गई, इसकी जांच कराई जा रही है। जिसकी भी लापरवाही या संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गठित एसओजी के साथ पहली बार कोई घटना हुई है। बदमाशों ने जिले की पुलिस को चुनौती दी है। बदमाशों की पहचान करने व उनकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी व कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को पड़ोसी प्रांत बिहार के सिवान जनपद में दबिश दी। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका है। एसओजी की एक टीम दोपहर बाद सिवान जनपद पहुंची और जहां गाडियों के पाट्र्स अलग कर बेच दिए जाते हैं।

एक नजर

सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला बोले- बंगाल में चल रहा है जंगलराज

कोलकाता। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच सुबह से ही छिटपुट हिंसा का दौर जारी है। इसी क्रम में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केसपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर जबरदस्त हमला किया गयाहै। स्थानीय कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां सड़क से गुजर रहे भाजपा प्रत्याशी के गाड़ी को लक्ष्य कर जमकर पत्थर, ईंट व डंडे बरसाए है। इसमें भाजपा प्रत्याशी के वाहन का शीशा टूटने के साथ गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। मीडिया की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। भाजपा ने हमले के पीछे तृणमूल का हाथ बताया है।

बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच छिटपुट हिंसा का दौर जारी है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के महिषादल में बूथ नंबर 177 पर भाजपा के बूथ आइटी इंचार्ज सुमन सेन पर हमले का मामला सामने आया है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर वहां तनाव का माहौल है। बंगाल में मतदान के बीच हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है की पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की महिला पोलिंग एजेंट पर हमला किया है। घायल महिला को अस्ªपताल ले जाया गया है। डेबरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का फंदे से झूलता हुआ शव बरामद हुआ है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा है कि भाजपा कार्यकर्ता की हª्या कर उसका शव फंदे से लटकाया गया है। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान सुबह 7 बजे से जारी है ताजा मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा विधानसभा क्षेत्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा और तृणमूल दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप-प्रª्यारोप लगा रहे हैं। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनके वोटरों को धमका रहे हैं।

मतदान शुरू होने से पहले तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कथित रूप से हत्या कर दी गई। 48 साल के उत्तम डोलुई केशपुर इलाके के हरिहरपुर के एक स्थानीय क्लब में थे की तभी 10-15 अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मिदनापुर के अस्पताल में ले जाते हुए रास्ªते में ही उनकी मौत हो गई।

डोलुई के परिवार ने आरोप लगाया कि भाजपा के ªगुंडों ने उस क्षेत्र में तनाव पैदा करने और मतदाताओं को मतदान से पहले डराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास हिंसा का सहारा लेने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वे केशपुर सीट जीतने के बारे में आश्वस्त हैं। इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है बता दें कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है।

गौरतलब है कि बंगाल में आज (1 अप्रैल) दूसरे चरण के मतदान में पांच जिलों उत्तर व दक्षिण 24 परगना, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर व बांकुड़ा की 30 विधानसभा सीटों पर 19 महिलाओं सहित कुल 171 प्रत्याशी मैदान में हैं।

सूनी गलियों में युवतियों से करता था छेड़खानी, सीसीटीवी में कैद हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस ने पकड़ा

जोधपुर। राजस्थान में जोधपुर के खंडा फलसा थाना क्षेत्र के सुखानंद बगीची इलाके में युवतियों से सुनसान जगह देख छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। सुनसान गलियों में युवतियों से छेड़छाड़ करने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्थानीय क्षेत्रवासियों ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए खंडा फलसा थाना ने 19 साल के युवक को पकड़ा है, उससे पूछताछ की जा रही है। जोधपुर के सुखानंद बगीची इलाके के रहवासियों ने खंडा फलसा थाना अधिकारी दिनेश लखावत को लिखित में शिकायत दी, जिसमें की एक मनचले युवक द्वारा राह चलती लड़कियों को कमर में हाथ डालकर पीछे से पकड़ कर भाग जाने और अश्लील हरकतें करने से अवगत कराया गया था।

इसके साथ ही स्थानीय निवासियों द्वारा अपने मकानों और तंग गलियों में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज में युवक द्वारा की गई अश्लील हरकतों की क्लिप को उपलब्ध कराया गया, जिसमें कि युवक द्वारा सुबह और शाम के समय सुनसान जगह पर मौका पाकर छेड़खानी करना पाया गया। संबंधित मामले की जानकारी पुलिस के संज्ञान में आते ही मामले में त्वरित कार्यवाही की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की शिनाख्त की और उसे पकड़ लिया। हालांकि पुलिस के द्वारा युवक की पहचान सुबह ही कर ली गई थी, लेकिन उस समय युवक के घर पर नहीं होने से पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। इसके बाद देर शाम पुलिस में युवक को पकड़ लिया और थाने लेकर आ गई। 19 वर्षीय युवक उसी क्षेत्र का युवक बताया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है।

इधर, इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) के ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर पद पर तैनात एक अधिकारी ने जयपुर के गांधी नगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। हालांकि मामला करीब दो साल पुराना है। जयपुर में तैनात अधिकारी डीके शर्मा ने दिल्ली की एक ट्रेवल एजेंसी से सितंबर, 2019 में अंडमान निकोबार घूमने जाने के लिए एयर इंडिया के टिकट बुक कराए थे। इसके बदले में करीब 2.55 लाख रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया था। ट्रेवल एजेंसी ने उन्हें टिकट भेज दिए, लेकिन शर्मा ने जब जांच की तो ये टिकट फर्जी निकले। इस पर उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क किया। कंपनी की तरफ से उन्हें भुगतान करने का आश्वासन दिया गया।

लव जिहाद के खिलाफ गुजरात में बनेगा कानून, विधानसभा में विधेयक पेश

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने लव जिहाद से संबंधित गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) अधिनियम 2021 विधानसभा में पेश कर दिया है। इसमें छल कपट लोग लालच अथवा छद्म नाम व धर्म बता कर विवाह करने वाले को 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। जबकि विवाह में मदद करने वाली संस्था अथवा संगठन के पदाधिकारियों को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने गुजरात विधानसभा में गुरुवार को गुजरात धर्म स्वातंत्र्य संशोधन अधिनियम 2021 को पेश किया इसमें धर्म परिवर्तन के आशय से विवाह करने वाले अथवा विवाह के बाद धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना गया है। इस तरह के विवाद से नाराज परिवार के कोई सदस्य माता-पिता भाई-बहन अथवा रिश्तेदार या विवाह व दत्तक रिश्तेदार पुलिस को शिकायत कर सकेगा।

गैर कानूनी तरीके से दूसरे धर्म के लड़के अथवा लड़की से विवाह कराने में मददगार परामर्श देने वाले को भी अपराध में भागीदार माना जाएगा। विवाह के बाद धर्म परिवर्तन कराना अथवा धर्म परिवर्तन के इरादे से ही शादी करना अपराध माना गया है। ऐसा अपराध करने वाले को 3 से 5 साल की सजा तथा ?2लाख के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है जबकि इसमें मददगार संस्था वह संगठन के पदाधिकारियों को 3 से 10 साल तक की सजा व ?5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है।

अभिषेक बनर्जी की भाजपा को चुनौती, प्रचार के लिए बंगाल आने वाले नेता दो मिनट बांग्ला बोलकर दिखाए

कोलकाता। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को भाजपा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। अभिषेक ने कहा कि, चुनाव प्रचार के लिए कई नेता दिल्ली से बंगाल आ रहे हैं। मैं उन्हें बंगाली में केवल दो मिनट बोलने के लिए चुनौती देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश के किसी भी हिस्से में हिंदी में बोलने के लिए तैयार हूं। अलीपुरद्वार में एक चुनावी जनसभा में अभिषेक ने कहा कि अमित शाह ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा घुसपैठिया शब्द का उल्लेख किया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जब बीएसएफ अंतरराष्ट्रीय सीमा की रखवाली कर रही है और यह अमित शाह के मंत्रालय में आता है। इसके लिए अमित शाह और बीएसएफ महानिदेशक को इस्तीफा देना चाहिए। अभिषेक ने कहा कि हर साल बंगाल केंद्र सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये भेजता है। मगर जब वे एम्फन राहत के लिए 1000 करोड़ रुपये भेजते हैं।

मोरीगांव जिले में असम विधानसभा चुनाव 2021 के दूसरे चरण के दौरान वोट डालने के लिए मतदाता थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरते हुए।

महबूबा के बड़बोलेपन से हाशिये पर पहुंची पीडीपी, पुराने नेताओं में अब उनके रिश्तेदार वीरी ही रहे

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़बोलापन ही अब उनके सियासी अस्तित्व के लिए संकट बन गया है। हालत यह है कि उनकी ही पार्टी के नेता तिरंगा थाम आगे बढने् के लिए उनका साथ छोड़ते हुए उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि अलग होने वालों को बदनाम करने के बजाय खास सलाहकारों से सावधान रहें अन्यथा पीडीपी का झंडा थामने के लिए उन्हें अपने सिवाय कोई दूसरा नहीं मिलेगा।

पीडीपी को फिर से खड़ा करने में जुटी महबूबा के साथ पुराने नेताओं में अब उनके रिश्तेदार या फिर पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान वीरी रह गए हैं। सिर्फ जम्मू में ही नहीं कश्मीर में भी पीडीपी के लगभग सभी जाने पहचाने चेहरे व दिग्गज नेता अन्य दलों में नया ठिकाना बना चुके हैं। पीडीपी का 1999 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गठन किया था तो कांग्रेस, नेकां समेत कई अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता उनके कारवां में शामिल हुए थे। पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल मुजफ्फर हुसैन बेग, तारिक हमीद करा, खलील बंड, पीर मोहम्मद हुसैन, दमन भसीन, वेद महाजन, त्रिलोक सिंह बाजवा, सुरेंद्र चौधरी, गुरु प्रसाद, अब्दुल हक खान, बशारत बुखारी, नजीर अहमद लावे, फैयाज मीर, यासिर रेशी सरीखे सभी नेता आज पीडीपी से अलग हो चुके हैं।

नजीर अहमद लावे ने कहा कि महबूबा जब तक अपने चाटुकारों और कुछ रिश्तेदारों के घेरे से बाहर नहीं आएंगी, उन्हें पता नहीं चलेगा कि वह क्या कर रही हैं। अगर कश्मीर में अलगाववाद और राष्ट्रध्वज की अवमानना से लोगों का दिल जीता जा सकता तो उनके पिता दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद ने न भाजपा के साथ सरकार बनाई होती और न कभी कांग्रेस से मिलकर हुकूमत की होती।

राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व के साथ ही मुकन्दरा हिल्स व केवलादेव राष्ट्रीय उघान में अब टाइगर सफारी महंगी हुई

जयपुर। राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व के साथ ही मुकन्दरा हिल्स व केवलादेव राष्ट्रीय उघान में प्रवेश बृहस्पतिवार से महंगा हो गया। अब पर्यटकों से 20 फीसदी तक अधिक प्रवेश शुल्क वसूला जाने लगा है। बृस्पतिवार को सुबह की पारी में टाइगर व अन्य वन्यजीव देखने पहुंचे देशी पर्यटकों से 1100 रुपया प्रवेश शुल्क लिया गया, पहले 1037 रुपए ही लिए जाते थे। विदेशी पर्यटकों से अब 2070 रुपए लिए जाएंगे, पहले 1847 लिए जाते थे।

वहीं देशी पर्यटकों की जिप्सी से अब 6600 और विदेशी पर्यटकों की जिप्सी के 12,420 रुपया प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। पहले देशी पर्यटकों की जिप्सी के 6600 एवं विदेशी पर्यटकों की जिप्सी के 12,420 लिए जाते थे। प्रवेश शुल्क के साथ ही जिप्सी चालक का चार्ज अलग से होगा, जिसे मिलाकर ही 20 तक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पिछले एक साल से विदेशी पर्यटक यहां भ्रमण के लिए नहीं आ रहे हैं। पिछले दो माह में रणथंभौर व सरिस्का टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं।

रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व के साथ ही मुकन्दरा हिल्स व केवलादेव राष्ट्रीय उघान में प्रवेश बृहस्पतिवार से महंगा हो गया। अब पर्यटकों से 20 फीसदी तक अधिक प्रवेश शुल्क वसूला जाने लगा है। बृस्पतिवार को सुबह की पारी में टाइगर व अन्य वन्यजीव देखने पहुंचे देशी पर्यटकों से 1100 रुपया प्रवेश शुल्क लिया गया, पहले 1037 रुपए ही लिए जाते थे। विदेशी पर्यटकों से अब 2070 रुपए लिए जाएंगे, पहले 1847 लिए जाते थे। प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहन लाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग ने तय कर रखा है कि प्रतिवर्ष पर्यटकों का प्रवेश शुल्क 10 फीसदी बढ़ाया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया गया था, इसलिए इस बार एक साथ 20 फीसदी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में 25 अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

उदयपुर की पीछोला झील में उतारे क्रूज का मामला सीएमओ पहुंचा, हाईकोर्ट निगरानी कमेटी ने भी उठाए सवाल

उदयपुर। शहर की लाइफलाइन पीछोला झील में उतारे गए जहाजनुमा क्रूज का विरोध लगातार उठता जा रहा है। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है और इस मामले में उदयपुर नगर निगम से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं, उदयपुर की झीलों के संरक्षण के लिए जिला स्तर पर बनी हाईकोर्ट निगरानी कमेटी ने झील में क्रूज उतारे जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर के विभिन्न संगठनों और पर्यावरणविदों ने झील में उतारे गए क्रूज को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत की थी।

जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने नगर निगम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। जिसमें पूछा गया है कि बिना लाइसेंस और पंजीयन के बिना क्रूज को झील में उतारने की अनुमति किसलिए दी गई। इस मामले में अवकाश का दिन चुनने को लेकर भी सवाल उठाया गया है। इधर, उदयपुर की झीलों के संरक्षण के लिए गठित हाईकोर्ट निगरानी कमेटी ने झील में क्रूज उतारने को लेकर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने नगर निगम से पूछा कि जब झीलों के पांच सौ मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है तो ऐसे में क्रूज निर्माण की अनुमति किन नियमों के तहत दी गई। पीछोला झील से उदयपुर की लगभग एक लाख की आबादी को प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई की जा रही है, ऐसे में डीजल से संचालित होने वाले होटलनुमा क्रूज को उतारने का फैसला क्या सही है? हाईकोर्ट निगरानी कमेटी के सदस्य डॉ. प्रवीण खंडेलवाल ने जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को पत्र लिखा है कि पीछोला-फतहसागर का पानी शहरवासियों के पेयजल का मुख्य स्त्रोत है। ऐसी स्थिति में क्रूज उतारने से पेयजल प्रदूषित होगा। उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए क्रूज संचालन जैसी गतिविधियों पर रोक और जल्द निगरानी कमेटी की बैठक बुलाकर चर्चा करने की मांग की। हाईकोर्ट निगरानी कमेटी के सदस्य एवं जलसंसाधन विभाग के रिटायर्ड एसई ज्ञानप्रकाश सोनी का कहना है कि झील संरक्षण के लिए तय नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है और मनोरंजन के साधन में रूप में देखा जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है।

नहीं मानी सरकार अब नीलामी से आवंटित होंगे शराब के लाइसेंस

जम्मू। केंद्र शासित बनने के बाद जम्मू कश्मीर में शराब के लाइसेंस अब नीलामी के जरिए आवंटित किए जाएंगे। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली देगा उसे यह लाइसेंस जारी होंगे। प्रशासन ने वीरवार को स्थानीय शराब विक्रेताओं के विरोध के बीच एक्साइज पॉलिसी को सार्वजानिक कर दिया है।

स्थानीय पुराने शराब लाइसेंस धारकों को यह उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच से वीरवार को शायद उन्हें कोई राहत मिल जाए और अदालत नीलामी के जरिए शराब के लाइसेंस आवंटित करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा देगी। शाम होते होते फैसला आया और अदालत ने ने भी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा।पुराने विक्रेताओं के शराब लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को समाप्त होनी थी, लेकिन नीलामी के जरिए लाइसेंस आंवटित करने की प्रक्रिया अभी शुरू न हो पाने के कारण एक्साइज विभाग ने वीरवार देर शाम एक सकुर्लर जारी कर पुराने विक्रेताओं को एक माह तक अपनी शराब की दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी। यह व्यवस्था पहली अप्रैल से लेकर पहली मई तक लागू होगी।

इसमें सभी ऐसे विक्रेताओं को ड्यूटी और फीस देनी होगी।आबकारी विभाग एक माह के अंदर नीलामी की सभी तैयारियों को पूरा करेगा।नई

एक्साइज पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, शराब की बिक्री के लिए अपनी बोली दे सकता है।बोली के आवेदन के लिए 25 हजार रुपये आवेदन फार्म के लिए रखे गए हैं, जो वापस नहीं होंगे । जबकि 5 लााख रुपये धरोहर राशि निर्धारित की गई है। बोलीदाता की उम्र 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज न हो।इएमडी राशि हरेक बोली के लिए अलग से जमा करवानी पड़ेगी। जिस बोलीदाता को बोली मिल जाती है, उसे शराब बेचने के लिए दुकान का इंतजाम अपनी तरफ से करना पड़ेगा।शराब का ठेका ई ऑक्शन पोर्टल https://jke&cisedept.auc-tiontiger.net के जरिए किए जाएंगे, ताकि आवंटन में पारदर्शिता बनी रहे। ई नीलामी का ब्यौरा और उसकी शर्तें बोलीदाताओं के लिए विभाग की आधिकारिक वेब साइट www.jke&cise.nic.in. पर उपलब्ध होगी।

विभाग इस बार पर्यटन स्थलों जहां पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, वहां पर शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में सहयोग करेगी। बर्शते की यह पर्यटन स्थल सरकार के हों। जैसे कि टूरिज्म विभाग, जेकेडीसी, टूरिज्म डवेल्पमेंट अर्थाटी। जेके केबल कार एसोसिएशन आदि शामिल होगें। यहां शराब की दुकानें खोलने से पहले वैरीफिकेशन करवाना जरूरी होगा। एक्साइज कमिशनर कमेटी गठित करेगा और इस कमेटी में सफल बोलीदाता को अपने दस्तावेजों की वैरीफिकेशन करवानी होगी।

इसी बीच, जम्मू कश्मीर वाइन एसोसिएशन के प्रवक्ता चरनजीत सिंह खालसा का कहना है कि सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को सार्वजनिक कर तानाशाही रवैये को दर्शा दिया है। उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के शराब विक्रेता बेरोजगार हो जाएंगे। जिनकी आमंदनी शराब की एक दुकान पर निर्भर है, उन्हें अब सड़कों पर आना पड़ जाएगा। यहां बता दे कि जम्मू संभाग में शराब के 219 विक्रेता है, जबकि कश्मीर में सिर्फ 4 विक्रेता। शराब विक्रेता नई आबकारी नीति को वापिस लेने के लिए कई बार उप राज्यपाल से गुहार लगा चुके है।

पश्चिम बंगाल चुनावः दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी पर लगाया आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे राउंड का मतदान चल रहा है। इससे पहले टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। पश्चिमी मिदनापुर जिले के केशपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की बुधवार रात को हत्या हो गई। दूसरे चरण से ठीक पहले सामने आई इस घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का हाथ बता रही है। केशपुर समेत प्रदेश की 30 विधानसभा सीटों से गुरुवार सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। इन सीटों में पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट कही जा रही नंदीग्राम भी शामिल है। यहां सीएम ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी ने उनके ही पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है।

पुलिस ने मृतक की पहचान उत्तम डोलुई के तौर पर की है, जिसकी उम्र 40 साल थी। पश्चिम मिदनापुर जिले के एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में चुनावी पैनल ने भी रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल दूसरे राउंड की वोटिंग में सबकी नजरें नंदीग्राम सीट पर ही हैं। ममता को यहां टक्कर दे रहे शुभेंदु अधिकारी ने कहा, %दीदी हार चुकी हैं। मैं जब बीजेपी का कार्यकर्ता था तो कहा था कि ममता बनर्जी 50,000 से ज्यादा वोटों से हार जाएंगी। आज मैं चुनाव में उम्मीदवार हूं और यह फैसला जनता पर छोड़ता हूं कि वह ममता बनर्जी को कितने अंतर से हराएंगे।

इस बीच वोटिंग के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ टीएमसी ने नंदीग्राम में वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है तो बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर हिंसा होने की आशंका जताई है। बुधवार को दोनों पार्टियों ने इलेक्शन कमिशन पहुंचकर शिकायत की थी। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि बीजेपी ने नंदीग्राम के गोकुलनगर और बोयल जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को बुलाया है। वहीं बीजेपी ने भी नंदीग्राम में टीएमसी की ओर से गुंडों को बुलाए जाने का आरोप लगाया था।

कुछ इलाकों से मिलीं मतदान के दौरान झड़प की खबरें

हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूनी संघर्ष के इतिहास के लिहाज से देखें तो दूसरे राउंड का मतदान भी काफी शांतिपूर्ण चल रहा है। कुछ इलाकों में मामूली झड़प की खबरें मिली हैं, लेकिन किसी बड़ी हिंसा की जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है, जबकि 2 मई को चुनाव नतीजे आने हैं। इसी दिन असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का भी परिणाम आएगा।

दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए पीएम मोदी ने दी रजनीकांत को बधाई

नई दिल्ली। साउथ के फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने वर्ष 2019 के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कई पीढ़ियों में लोकप्रिय। विभिन्न भूमिका निभाने वाले। एक स्थायी व्यक्तित्व... आपके लिए रजनीकांत हो सकता है। यह बेहद खुशी की बात है कि थलाइवा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बधाई।

आपके बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर रजनीकांत की तस्वीर के साथ पोस्ट किया, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2019 का दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड भारतीय सिनेमा के इतिहास के महान एक्टर्स में से एक रजनीकांत को दिया जा रहा है। बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीनराइटर उनका योगदान आइकॉनिक रहा है। साथ ही उन्होंने जूरी आशा भोसले, सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन और बिस्वजीत चटर्जी को धन्यवाद दिया।

2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था सम्मान 2018 का दादा साहेब फाल्के सम्मान अमिताभ बच्चन को मिला था। उस वक्त रजनीकांत ने बिग बी को बधाई दी थी। रजनीकांत ने ट्वीट किया था, आप इस सम्मान के योग्य हैं।

असम-अरुणाचल में भारी बारिश के आसार, दिल्ली से सटे राज्यों में भी गर्मी से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। भारत मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण अंडमान सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से आज अंडमान-निकोबार क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण में स्थित है। यह अंडमान सागर के मध्य भागों पर अधिक चिह्नित होने की संभावना है और अगले 48 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में रहने की संभावना है।

इसके प्रभाव में, अगले पांच दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों पर व्यापक वर्षा की संभावना है और आज भारी वर्षा की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान द्वीपों पर हल्की और तेज़ हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में न जाएं। बंगाल की खाड़ी और अन्य अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों से दक्षिण-पश्चिम की तेज़ हवाओं के प्रभाव के तहत, शुक्रवार तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में गरज और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज भी भारी बारिश की संभावना है। यह अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में निचले इलाकों में भूस्खलन या मडस्लाइड और बाढ़ का कारण बन सकता है।

अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जिससे हीटवेव की स्थिति में गिरावट आ सकती है। अगले 48 घंटों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार) चलने की संभावना है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख के सती देवी ने कहा, बहुत तेज हवाओं के कारण हीटवेव की स्थिति 2-3 दिनों तक रहने की संभावना नहीं है।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सुननी पड़ी बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार

मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह उच्च न्यायालय में दायर अपनी जनहित याचिका पर आज खुद ही घिरते नजर आए। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आपके सामने ही अपराध होता रहा और आपने एफआइआर क्यों हीं दर्ज करवाई? फिलहाल उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय से लौटा दिए जाने के बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनके वकील विक्रम ननकानी ने इस याचिका में कहा कि चूंकि इस मामले में कई बड़े लोग व राज्य सरकार के विभाग शामिल हैं, इसलिए उच्च न्यायालय को इस मामले की जांच राज्य के बाहर की सीबीआइ जैसी एजेंसी को सौंपना चाहिए।

ननकानी ने इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले भी कोर्ट को दिखाई। लेकिन मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या इस मामले में आपने एफआइआर दर्ज कराई है? बिना एफआइआर के हम किसी भी जांच एजेंसी को जांच का आदेश कैसे दे सकते हैं? न्यायमूर्ति दत्ता ने ननकानी को रास्ता भी सुझाया कि यदि आप सीधे एफआइआर दर्ज नहीं कराना चाहते हैं तो सीआरपीसी की धारा 156 के तहत मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, उनके आदेश पर एफआइआर दर्ज हो जाएगी।

इस पर जब ननकानी ने कहा कि यह एफआइआर तो मुंबई पुलिस में दर्ज होगी, सीबीआइ में नहीं। हम चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते। तो न्यायमूर्ति दत्ता ने फटकारते हुए कहा कि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो कानून से ऊपर नहीं हो सकते। क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? आपको शर्म आनी चाहिए कि आज आदमी भी एफआइआर करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है।

सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी भी मुख्य न्यायाधीश को संतुष्ट नहीं कर सके। आशुतोष ने बताया कि राज्य सरकार ने खुद गृहमंत्री के आग्रह पर गृहमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपये की वसूली करवाने के प्रकरण की जांच करवाने का फैसला किया है और इसके लिए एक समिति भी बना दी है।

सूरज बड़जात्या की फिल्म से होगी सनी देओल के छोटे बेटे के फिल्मी करियर की शुरुआत

अभिनेता से राजनेता बने सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल फिल्म निर्माता सूरज आर बड़जात्या की अगली फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। निर्माताओं ने बुधवार को यह घोषणा की। इस फिल्म से सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश एस बड़जात्या लेखक और निर्देशक के तौर पर करियर शुरू कर रहे हैं। यह फिल्म सूरज बड़जात्या की प्रोडक्शन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन की 59वीं फिल्म होगी। सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल 'पल पल दिल के पास' से फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके हैं। राजवीर ने ब्रिटेन में थियेटर की पढ़ाई की है और सहायक निर्देशक के रूप में वह काम कर चुके हैं। वह रंगमंच और फिल्म निर्देशक फिरोज अब्बास खान के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब्बास 'मुगल-ए-आजम' और 'तुम्हारी अमृता' जैसे नाटकों का निर्देशन करने के लिए जाने जाते हैं। अवनीश ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म में राजवीर को लेने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि वह मेहनती हैं। उन्होंने कहा, '' हमने इस फिल्म के बारे में जितनी ज्यादा बातें की, उतना मैं राजवीर को इस फिल्म के नायक के रूप में देखने लगा।'' अभी तक इस फिल्म का नाम तय नहीं हुआ है। इसकी शूटिंग इस साल जुलाई से शुरू होने की संभावना है और 2022 में यह रिलीज होगी।

'आरआरआर' से अजय देवगन के किरदार को लेकर सामने आयी बड़ी जानकारी

एसएस राजामौली की 'आरआरआर' साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और आलिया भट्ट भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कुछ दिन पहले, निर्माताओं ने उनके जन्मदिन पर आलिया और राम चरण के फर्स्ट लुक पोस्टर का रिलीज किया था। अब मेकर्स अजय देवगन के फर्स्ट लुक को मोशन पोस्टर के रूप में रिलीज करने के लिए तैयार है। अभिनेता ने अपने फर्स्ट लुक पोस्टर के बारे में घोषणा करने के लिए अपने ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने खुलासा किया कि उनका फर्स्ट लुक 2 अप्रैल को रिलीज होगा। उन्होंने ट्वीट किया, 'यह एक रोमांचक अनुभव रहा है। काम के मोर्चे पर, अभिनेता पिछले कुछ हफ्तों से 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की शूटिंग में व्यस्त हैं। यह फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ दो दशकों के बाद उनके ऑन-स्क्रीन पुनर्मिलन को चिह्नित करती है। एसएलबी द्वारा अभिनीत, फिल्म में आलिया भट्ट प्रमुख भूमिका में हैं। आरआरआर में जूनियर एनटीआर और श्रिया सरन भी शामिल हैं।

अभिनेत्री राधिका आप्टे 'मिसेज अंडरकवर' में जासूस का किरदार अदा करेंगी

अभिनेत्री राधिका आप्टे 'मिसेज अंडरकवर' फिल्म में जासूस का किरदार अदा करने जा रही हैं। फिल्म निर्माताओं ने रविवार को यह घोषणा की। 'इंदु की जवानी' फिल्म का निर्देशन करनेवाले अबीर सेनगुप्ता इस फिल्म के साथ निर्माता के रूप में करियर की नई पारी शुरू कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म के साथ लेखक-निर्माता अनुश्री मेहता निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रही हैं। इस फिल्म में आप्टे के साथ अभिनेता सुमीत व्यास नजर आएंगे।
आप्टे ने कहा कि मेहता ने जब इस फिल्म की पटकथा के साथ उनसे संपर्क किया तो वह इस कहानी के 'नयापन' से बेहद प्रभावित हुईं। फिल्म के पोस्टर में वह 'एक घरेलू महिला के रूप में बंदूक के साथ नजर' आईं। अभिनेत्री ने एक बयान में कहा, '' हम सभी फिल्म का भाव पोस्टर के जरिए दिखाना चाहते थे और मैं यह कहना चाहूंगी कि हमने ऐसा किया भी। मैं अब इस इंतजार में हूं कि दर्शक इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं।'' मेहता ने कहा कि दर्शकों के बीच फिल्म का पहला लुक जारी करना 'स्वप्निल' अनुभव था।

अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के फैंस को लगा बड़ा झटका! चेहरे से जुड़ी बड़ी खबर

मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण कई बड़ी फिल्मों की रिलीज रुक गयी थी। अब साल भर बार लॉकडाउन खत्म हुआ था और जिंदगी वापस पटरी पर लौट ही रही थी कि एक बार फिर कोविड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। हालात एक बार फिर गंभीर है। कोरोना वायरस से 50 हजार से भी ज्यादा केस एक दिन में आने लगे हैं। साथ ही सेकड़ों लोग की मौत की खबरें भी रोजाना आ रही हैं। मुंबई में हालात काफी खराब हो गये हैं। ऐसे में दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही हैं। रूमी जाफ़री द्वारा निर्देशित,आनंद पंडित की फिल्म चेहरे का जब से निर्माताओं ने पोस्टर, टीज़र और ट्रेलर जारी किए हैं तब से न केवल दर्शकों बल्कि आलोचकों से भी इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। चेहरे में पहली बार बड़े पर्दे पर सुपरस्टार कलाकारों की टुकड़ी देखने की प्रत्याशा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पिछले साल लॉकडाउन के बाद, कई फिल्म निर्माता 2021 में अपनी आगामी फिल्मों की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। भले ही देश भर में थिएटर और अन्य प्रतिष्ठान सुचारू रूप से काम कर रहे हों, लेकिन अचानक कोविड-19 मामलों में स्पाइक चिंता का विषय है। जिस स्थिति से देश गुजर रहा है उसे देखते हुए और प्रशंसकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म चेहरे की रिलीज को स्थगित करने का फैसला किया है। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी अभिनीत, मिस्ट्री-थ्रिलर चेहरे 9 अप्रैल, 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। अपने इस फैसले के बारे में बात करते हुए निर्माता आनंद पंडित कहते हैं 'हमारे दर्शकों और प्रशंसकों की स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमने अपनी फिल्म चेहरे को स्थगित करने का फैसला किया है। टीम ने इसे एक महान सिनेमाई बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। अनुभव और हम अपने दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में सुरक्षित रूप से आने का इंतजार कर रहे हैं। 'इमरान हाशमी ने अपने इंस्टाग्राम पर आधिकारिक बयान साझा किया जिसमें लिखा था, 'कोविड़ - 19 के बढ़ते मामलों और नए दिशानिर्देशों के कारण, हम 9 अप्रैल को अपनी फिल्म चेहरे को सिनेमाघरों में रिलीज़ करने में असमर्थ हैं और अगली सूचना तक स्थगित करने का फैसला किया है।'

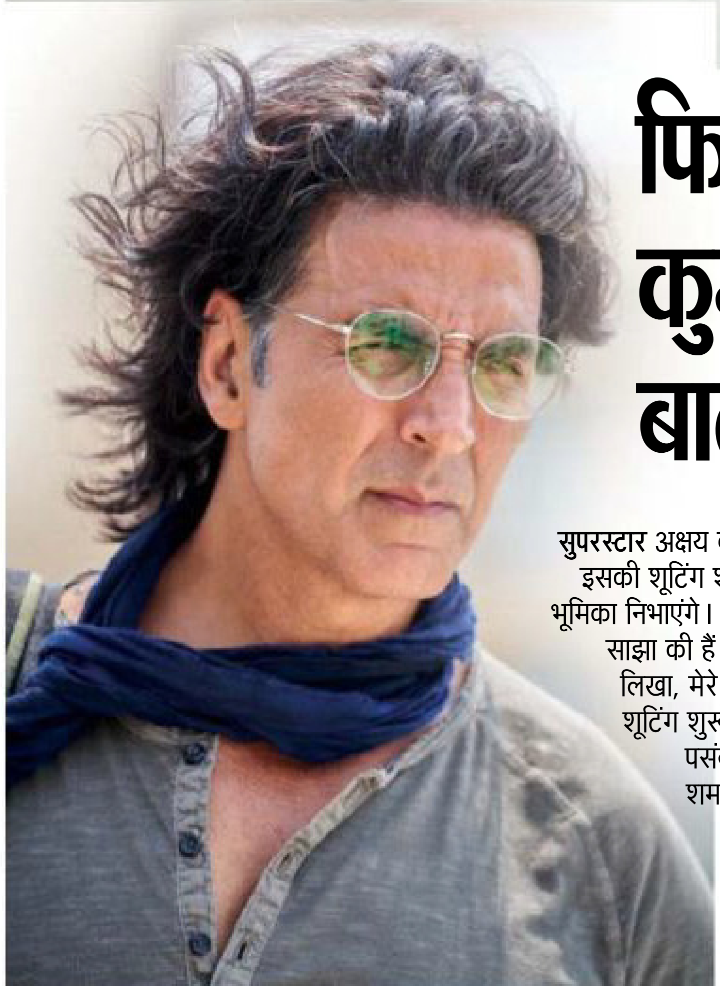

फिल्म 'राम सेतु' से अक्षय कुमार का लुक आउट! बड़े बालों के साथ दिखाया टशन

सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म 'राम सेतु' से अपने लुक को साझा किया, क्योंकि उन्होंने इसकी शूटिंग शुरू कर दी थी। अभिनेता ने यह भी खुलासा किया कि वह फिल्म में एक पुरातत्वविद् की भूमिका निभाएंगे। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म से जुड़ी तस्वीर के साथ कई जानकारी भी साझा की हैं। अक्षय ने फिल्म में अपने किरदार की एक तस्वीर के साथ एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, मेरे लिए सबसे खास फिल्मों में से एक बनाने की यात्रा आज से शुरू हो रही है। रामसेतु की शूटिंग शुरू! फिल्म में एक पुरातत्वविद् की भूमिका निभा रहा हूं। इस लुक पर आपके विचार सुनना पसंद करेंगे? यह हमेशा मेरे लिए मायने रखता है।' फिल्म को 'तेरे बिन लादेन' के अभिषेक शर्मा द्वारा बनाया जा रहा है। अक्षय के अलावा, इसमें जैकलीन फर्नांडीज और नुसरत भरुचा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं इसके अलावा, अक्षय के पास बहुत ही दिलचस्प फिल्मों की लाइन-अप है जिनमें से एक 'बेल बॉटम' है जिसमें हुमा कुरैशी, लारा दत्ता और वाणी कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। उन्हें 'बच्चन पांडे' में भी देखा जाएगा, जहां वह कृति सेनन के साथ मुख्य भूमिका में फिर से नज़र आएंगे। इसमें अरशद वारसी भी अहम भूमिका में हैं।

आईपीएल में धोनी की होगी दमदार वापसी, पिछले साल की असफलता भुलाकर वापसी करने उतरेगा सीएसके

चेन्नई।(एजेंसी)।

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पिछले साल के दुस्वप्न को भुलाकर इस बार दमदार वापसी करने की कोशिश करेगी। संयुक्त अरब अमीरात में खेले गये 2020 के टूर्नामेंट में तीन बार की चैंपियन सीएसके प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही थी। यह टूर्नामेंट के इतिहास में पहला अवसर था जबकि धोनी की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पायी थी। टीम नौ अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल में नये सिरे से शुरुआत करने के लिये उतरेगी। उसका पहला मैच 10 अप्रैल को मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। सीएसके का मजबूत पक्ष उसके पास अनुभवी खिलाड़ियों का होना है जो मुश्किल परिस्थितियों में टीम की नैया पार लगाते रहे हैं।

धोनी का प्रेरणादायी नेतृत्व टीम का एक अन्य सकारात्मक पहलू है। सुरेश रैना की वापसी से उसकी बल्लेबाजी मजबूत हुई है। पिछले साल उसके बल्लेबाज नहीं चल पाये थे। रैना के अलावा फाफ डुप्लेसिस, धोनी, अंबाती रायुडु, रविंद्र जडेजा, सैम करेन, मोईन अली और रुतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में सीएसके की बल्लेबाजी मजबूत नजर आती है। उसका गेंदबाजी आक्रमण भी अच्छा है जिसमें लुंगी एनगिडी, शार्दुल ठाकुर, सैम करेन, इमरान ताहिर, जडेजा और दीपक चहर जैसे गेंदबाज हैं। सीएसके टीम में उम्रदराज खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के तेजतर्रार प्रारूप टी20 में यह उसकी कमजोरी साबित हो सकती है। धोनी, रैना, रायुडु और ताहिर जैसे उसके खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में भी नहीं खेलते। ऐसे में मैच अभ्यास की कमी टीम को भारी पड़ सकती है। इसके अलावा धोनी के फिनिशर के रूप में पहले जैसी भूमिका नहीं निभा पाने से भी टीम को नुकसान हुआ है। आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का आईपीएल से हटने का निर्णय भी सीएसके के लिये करारा झटका है। इसके अलावा जडेजा भी चोट के कारण लंबे विश्राम के बाद वापसी कर रहे हैं और देखना होगा कि वह कितनी जल्दी लय हासिल करते हैं।

वेस्टइंडीज के अनुभवी आलराउंडर ड्वेन ब्रावो का वापसी पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना और उनकी चोट भी सीएसके के लिये चिंता का विषय होगा। इस बार आईपीएल मैच तटस्थ स्थलों पर खेले जाएंगे। सीएसके अपने स्पिन विभाग पर काफी निर्भर रहा है और ऐसे में उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। विशेषकर मुंबई के विकेटों पर जहां तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। सीएसके पिछले सत्र की असफलता से वापसी करने के लिये प्रतिबद्ध है लेकिन इसके लिये उसे शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जल्द से जल्द से अच्छा टीम संयोजन तैयार करना भी उसके लिये महत्वपूर्ण होगा। सीएसके को पिछले साल अपनी कमजोर बल्लेबाजी के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। यदि इस विभाग में उसने सुधार नहीं किया तो फिर उसकी वापसी की संभावना कम हो जाएगी। यही नहीं टीम को जीत दिलाने के लिये उसके तेज गेंदबाजों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस प्रकार है : महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), सुरेश रैना, अंबाती रायुडु, केएम आसिफ, दीपक चहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डुप्लेसिस, इमरान ताहिर, एन जगदीसन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल सेंटनर, रविंद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, सैम करेन, आर साई किशोर, मोइन अली, के गौतम, चेतेश्वर पुजारा, हरिशंकर रेड्डी, भगत वर्मा, सी हरि निशांत।

आरसीबी से जुड़ने चेन्नई पहुंचे कप्तान विराट कोहली, सात दिन पृथकवास में रहेंगे

चेन्नई। (एजेंसी)।

भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के कप्तान विराट कोहली इस इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी से जुड़ने के लिए गुरुवार को यहां पहुंच गए लेकिन टीम से जुड़ने से पहले उन्हें सात दिन के पृथकवास से गुजरना होगा। नौ अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी सत्र के लिए आरसीबी की टीम मंगलवार से ही ट्रेनिंग शिविर में हिस्सा ले रही है। कोहली की मास्क पहने हुए तस्वीर साझा करते हुए आरसीबी ने ट्वीट किया, ''कप्तान विराट कोहली चेन्नई पहुंच चुके हैं।'' टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में आरसीबी का सामना नौ अप्रैल को यहां गत चैंपियन मुंबई इंडियन्स से होगा। वर्ष 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही आरसीबी से जुड़े हुए कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में भारत के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला जीतने के बाद सोमवार को जैविक रूप से सुरक्षित माहौल से बाहर निकल गए थे।

कोहली इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला से पहले जनवरी के अंत से ही विभिन्न शहरों में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल का हिस्सा थे। वह चार टेस्ट, पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की भारतीय टीम का हिस्सा रहे। आरसीबी के एक अन्य अहम सदस्य दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी गुरुवार को आरसीबी के जैविक रूप से सुरक्षित माहौल से जुड़ गए। वर्ष 2011 में पहली बार आरसीबी से जुड़ने के बाद से ही डिविलियर्स टीम के अहम सदस्य रहे हैं। मुख्य कोच साइमन कैटिच भी तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के साथ पृथकवास से बाहर आ गए हैं। इस बीच आरसीबी की टीम ने एक और अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया।

फिन एलेन के तूफानी अर्धशतक की मदद से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया

ऑकलैंड।(एजेंसी)।

फिन एलेन के तूफानी अर्धशतक और मार्टिन गुप्टिल के साथ उनकी पहले विकेट के लिये 85 रन की साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने गुरुवार को यहां बारिश से प्रभावित तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 65 रन से करारी शिकस्त देकर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। बारिश के कारण यह मैच 10-10 ओवरों का कर दिया जिसमें पावरप्ले तीन ओवर का था और एक गेंदबाज को दो - दो ओवर करने थे। न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी के लिये आमंत्रित किये जाने के बाद 10 ओवर में चार विकेट पर 141 रन ठोक दिये। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 9.3 ओवर में 76 रन पर सिमट गयी।

न्यूजीलैंड ने पहला मैच 66 रन से और दूसरा मैच 28 रन से जीता था। फिन एलेन ने 29 गेंदों पर 10 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 71 रन बनाये। उन्होंने गुप्टिल (19 गेंदों पर 44, एक चौका, पांच छक्के) के साथ केवल 5.4 ओवर में 85 रन जोड़ दिये थे। एलेन ने मात्र 18 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। यह उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहला पचासा है। ग्लेन फिलिप ने दो छक्कों की मदद से 14 रन बनाये जबकि डेरेल मिचेल ने 11 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश ने इसके जवाब में टिम साउदी (15 रन देकर तीन) के पहले ओवर में सौम्य सरकार (10) और

कप्तान लिट्टन दास (शून्य) के विकेट गंवा दिये। इसके बाद लेग स्पिनर टॉड एस्टल (13 रन देकर चार विकेट) पर लंबे शॉट लगाने के प्रयास में बांग्लादेश के बल्लेबाज पवेलियन लौटे। बांग्लादेश के तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे। इनमें सरकार के अलावा सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नईम (19) और मोसादेक हुसैन (13) शामिल हैं। इससे पहले मैच स्थानीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होना था लेकिन बारिश के कारण आखिर में रात नौ बजे टॉस संभव हो पाया। न्यूजीलैंड ने वनडे श्रृंखला में भी 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।

खेल मंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों की तैयारी की समीक्षा की

नयी दिल्ली।(एजेंसी)।

तोक्यो ओलंपिक के आयोजन में अब जब तीन महीने से कुछ अधिक का समय बचा है तब खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और राष्ट्रीय खेल महासंघों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके खिलाड़ियों की तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार को हुई इस बैठक में भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के शीर्ष अधिकारियों, आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा, महासचिव राजीव मेहता और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के प्रमुख आदिले सुमारिवाला ने हिस्सा लिया।

रीजीजू ने ट्वीट किया, ''अधिकारियों और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा, महासचिव राजीव मेहता और अन्य सदस्यों के साथ साइ मुख्यालय में ओलंपिक की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले अपने खिलाड़ियों का संक्षिप्त और आकर्षक वीडियो बनाएंगे।'' पता चला है कि बैठक के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की तोक्यो खेलों की तैयारियों की नियमित समीक्षा की गई। तोक्यो खेलों का आयोजन 23 जुलाई से आठ अगस्त के बीच होना है। सूत्रों के अनुसार ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को कोविड-19 टीका लगाने के मुद्दे पर बैठक में चर्चा नहीं की गई।

पंत होंगे टीम इंडिया के अगले धोनी, इस पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

सबसे मुश्किल दौर में टीम इंडिया की कप्तानी संभाल चुके और सर्वाधिक 3 विश्वकप में भारतीय क्रिकेट की कमान संभालने वाले हैदराबाद के बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने विकेटकीपर ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है।

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन का मानना है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पिछले कुछ महीनों में सभी प्रारूपों में स्वयं को साबित किया है और वह भविष्य में भारतीय टीम की कमान संभालने के दावेदारों में सबसे आगे होंगे।

श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के कारण बाहर हो जाने से पंत इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई करेंगे।

अजहरूद्दीन ने ट्वीट किया, ''ऋषभ पंत के लिये पिछले कुछ महीने शानदार रहे और उन्होंने सभी प्रारूपों में स्वयं को स्थापित किया। यदि चयनकर्ता निकट भविष्य में भारतीय कप्तानी के दावेदारों में उन्हें सबसे आगे पाते हैं तो यह हैरानी भरा नहीं होगा। उनकी आक्रामक क्रिकेट से भारत को आने वाले समय में फायदा होगा। ''

इस 23 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ महीनों में तीनों प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन किया।

पंत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में 97 और नाबाद 89 रन बनाये तथा भारत की 2-1 से जीत में अहम भूमिका निभायी। उन्होंने इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में शतक जड़ा था। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला में उन्होंने लगातार मैचों में अर्धशतक लगाये थे।

बल्लेबाजी में किए गए शानदार प्रदर्शन के कारण दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिली।

जनवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत चुके पंत ने इसे चुनौती माना और कहा कि वह चाहेंगे कि उनकी कप्तानी में आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन एक पायदान आगे हो सके। गौरतलब है कि पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता रही थी और फाइनल में मुंबई इंडियन्स से हार गई थी।

बहरहाल अगर अजहरुद्दीन का बयान आगे चल कर सच होता है तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऋषभ पंत टीम इंडिया की कमान संभालने वाले दूसरे विकेटकीपर हो सकते हैं। हालांकि पंत को इसके लिए कई सालों तक इंतजार भी करना पड़ सकता है।

इसका कारण है बोर्ड का कोहली की कप्तानी में अटूट विश्वास। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत एशिया कप 2018 में विजयी हुआ था और हाल ही में बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी लेकिन फिर भी कोहली को इन दोनों फॉर्मेट का कप्तान बनाए रखा।

यही नहीं पंत को कप्तानी मिलने से पहले कई वरिष्ठ खिलाड़ी भी लाइन में होंगे, इनमें मुख्यत रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर , केएल राहुल जैसे बड़े नाम है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अजहरुद्दीन की भविष्यवाणी सही होती है या नहीं।

चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड आईपीएल से हटे, यह है कारण

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड इस साल एशेज और टी20 विश्व कप के लिये स्वयं को तरोताजा रखने के लिये इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से हट गये हैं। हेजलवुड को आईपीएल में खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के अन्य खिलाड़ियों के साथ रवाना होकर सीएसके से जुड़ना था लेकिन उन्होंने नौ अप्रैल से 30 मई तक चलने वाली इस टी20 लीग से हटने और अगले दो महीने घर में बिताने का निर्णय किया। इस 30 वर्षीय गेंदबाज ने पिछले साल यूएई में खेले गये आईपीएल में सीएसके की तरफ से तीन मैच खेले थे। हेजलवुड ने क्रिकेट.काम.एयू से कहा, ''हमने पिछले 10 महीने जैव सुरक्षित वातावरण में बिताये हैं और इस बीच अलग अलग समय में पृथकवास में भी रहना पड़ा, इसलिए मैंने क्रिकेट से कुछ समय के लिये विश्राम लेने तथा अगले दो महीने ऑस्ट्रेलिया में अपने घर में बिताने का निर्णय किया। '' उन्होंने कहा, ''हमारा आगे व्यस्त कार्यक्रम है और मैं आस्ट्रेलिया की तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहता हूं। '' इस तेज गेंदबाज से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जोश फिलिप और सनराइजर्स हैदराबाद के मिशेल मार्श ने भी आईपीएल से हटने का निर्णय किया। रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलिया के कुछ अन्य खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट से हटने पर विचार कर सकते हैं।

2023 महिला विश्व कप के लिए नौ मेजबान शहरों की हुई घोषणा

सिडनी। महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 के मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नौ शहरों में खेले जाएंगे। पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा जबकि फाइनल सिडनी के स्टेडियम आस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों एक - एक सेमीफाइनल की मेजबानी करेंगे। यह पहला विश्व कप होगा जिसे दो अलग अलग परिसंघों के सदस्य संयुक्त तौर पर आयोजित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया 2006 में एशियाई परिसंघ से जुड़ गया था जबकि न्यूजीलैंड ओसेनिया परिसंघ का सदस्य है। यही नहीं इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। इससे पहले 2019 तक 24 टीमों के बीच विश्व कप खेला जाता रहा। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के अनुसार महिला विश्व कप 2023 के मैच एडिलेड, ऑकलैंड, ब्रिस्बेन, ड्यूनेडिन, हैमिल्टन, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी और वेलिंगटन में खेले जाएंगे।

चेन्नई में आरसीबी के बायो-बबल से जुड़े एबी डिविलियर्स, आईपीएल के लिए तैयार 'महामानव'

चेन्नई। दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स नौ अप्रैल से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से पहले गुरुवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के बायो बबल (जैव सुरक्षित वातावरण) से जुड़ गये। डिविलियर्स 2011 से आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं और वह इस टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं।

आरसीबी ने ट्वीट किया, ''महामानव पहुंच चुका है। एबी डिविलियर्स चेन्नई में आरसीबी के बायो बबल से जुड़ गये हैं। '' डिविलियर्स ने 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था लेकिन वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में नियमित तौर पर सक्रिय हैं। आरसीबी के मुख्य कोच साइमन कैटिच और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी पृथकवास का समय पूरा करके टीम से जुड़ गये हैं। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी ने मंगलवार से नौ दिन का अनुकूलन शिविर शुरू किया है। लीग के पहले मैच में आरसीबी का सामना मुंबई इंडियन्स से होगा।

3 महीने से मैदान से बाहर रहे उमेश यादव अपनी पहली फैंचाइजी से वापस जुड़कर हैं खुश

मुंबई।(एजेंसी)।

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज उमेश यादव पृथकवास में सात दिन बिताने के बाद नौ अप्रैल से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी टीम में जाने पहचाने चेहरों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये तैयार हैं।

दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले 33 वर्षीय यादव की इस टीम में वापसी हुई है। उन्हें फरवरी की नीलामी में उनके आधार मूल्य एक करोड़ रुपये में खरीदा गया था।उमेश ने कहा, ''एक सप्ताह तक पृथकवास पर रहने के बाद मैदान पर उतरना और खिलाड़ियों के साथ कुछ समय बिताना अच्छा रहा।'' दिल्ली कैपिटल्स की विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा, ''मैं गेंद थामने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं। मैं टीम के लिये निश्चित तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और हर दिन अपने खेल में निखार लाने की कोशिश करूंगा। ''उमेश ने आईपीएल में 121 मैचों में 119 विकेट लिये हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स के शिविर में उन्हें घर जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा, ''मैंने दिल्ली टीम की तरफ से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी, इसलिए दिल्ली फ्रेंचाइजी मुझे घर जैसी लगती है। मैं टीम के कई खिलाड़ियों को जानता हूं। मैं पिछले कुछ समय से इशांत शर्मा, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलता रहा हूं।''उमेश ने कहा, ''ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी नयी टीम से जुड़ रहा हूं। मैं दिल्ली कैपिटल्स के शिविर में सहज महसूस कर रहा हूं। '' ऑस्टि्र्लया के खिलाफ बोर्डर गावस्कर सीरीज के अंतिम दो टेस्ट से उमेश यादव को चोट के कारण बाहर बैठना पड़ा था। उनकी मांसपेशियों में खिंचाव था और मेलबर्न टेस्ट के बाद सिडनी और ब्रिस्बेन टेस्ट में वह टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे और रिहैबिलिटेशन के लिए घर लौट आए थे। यादव को ऑस्टि्र्लयाके खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन के खेल के दौरान पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का आठवां और अपना चौथा ओवर करते समय उमेश तेज दर्द के कारण लड़खड़ा गए थे। उन्होंने तुरंत ही चिकित्सा टीम को मैदान पर बुलाया था। इसके बाद वे लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। इस मैच की पहली पारी में वह कोई भी विकेट नहीं निकाल पाए थे पर दूसरी पारी में जो बर्न्स का विकेट निकाला था। हाल ही में भारत बनाम इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में दूसरे टेस्ट के बाद वह फिटनेस पास कर चुके थे लेकिन तीसरे डे नाइट टेस्ट

और अंतिम टेस्ट में वह अंतिम ग्यारह का हिस्सा नहीं बन पाए। कुल 3 महीने बाद उमेश यादव आईपीएल के माध्यम से मैदान पर वापस लौटेंगे।